वर्ष 13 • अंक 25 • 14 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

मंगलवार 17 मार्च 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

`एक जिंस एक एक्सचेंज' का प्रस्ताव

अनिल अंबानी पृष्ठ 4

अनिल अंबानी को ईडी ने 19 मार्च को किया तलब

डॉलर रु. 74.30 ▲ 40 पैसे | यूरो रु. 82.90 ▲ 30 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 39835 ▼ 2014 रुपये | सेंसेक्स 31390.10 ▼ 2713.40 | निफ्टी 9197.40 ▼ 757.80 | निफ्टी फ्यूचर्स 9118.50 ▼ 79.00 | ब्रेंट क्रूड 28.90 डॉलर ▼ 04.70 डॉलर

मंदी की आहट से सहमा बाजार

- कोरोनावायरस के कारण बाजारों में चौतरफा बिकवाली
- अंकों के लिहाज से बाजार में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट
- कोरोनावायरस से वैश्विक मंदी की चिंताओं ने सिर उठाया

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 16 मार्च

कोरोनावायरस के कारण वैश्विक मंदी की आशंका से चौतरफा बिकवाली से शेयर बाजार आज औंधे मुंह गिर गए। सेंसेक्स ने 2,713 अंक यानी करीब 8 फीसदी का गोता लगाकर 31,390 अंक पर पहुंच गया जो अक्टूबर 2017 के बाद इसका न्यूनतम स्तर है। निफ्टी 50 भी 646 अंक यानी 7 फीसदी टूटकर 9,3,09 अंक पर बंद हुआ। रुपया आधा फीसदी कमजोर होकर 74.27 रुपये प्रति डॉलर के भाव पर बंद हुआ जो 15 महीने में उसका सबसे निचला स्तर है।

अधिकांश एशियाई बाजारों में करीब 3 फीसदी तक गिरावट आई जबकि भारत की कारोबारी अवधि के दौरान यूरोपीय बाजारों ने 8 फीसदी तक का गोता लगाया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के दरों में भारी कटौती के बावजूद एसऐंडपी 500 सूचकांक में वायदा निचली सीमा को छू लिया।

रविवार को अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने नीतिगत ब्याज दर में एक फीसदी की बड़ी कटौती करके इसे करीब शून्य प्रतिशत कर दिया था। इसके अलावा उसने 700 अरब डॉलर के बॉन्ड खरीदने का भी निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक सहित दूसरे केंद्रीय बैंकों ने भी आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हरसंभव उपाय करने का आश्वासन दिया।

एवेंडस कैपिटल ऑल्टरनेट स्ट्रैटजीज के मुख्य कार्याधिकारी एंड्रयू हॉलैंड ने कहा, 'कोरोनावायरस जिस तरह विकराल रूप ले रहा है कि उससे वैश्विक मंदी की आशंका गहराने लगी है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर होगा।'

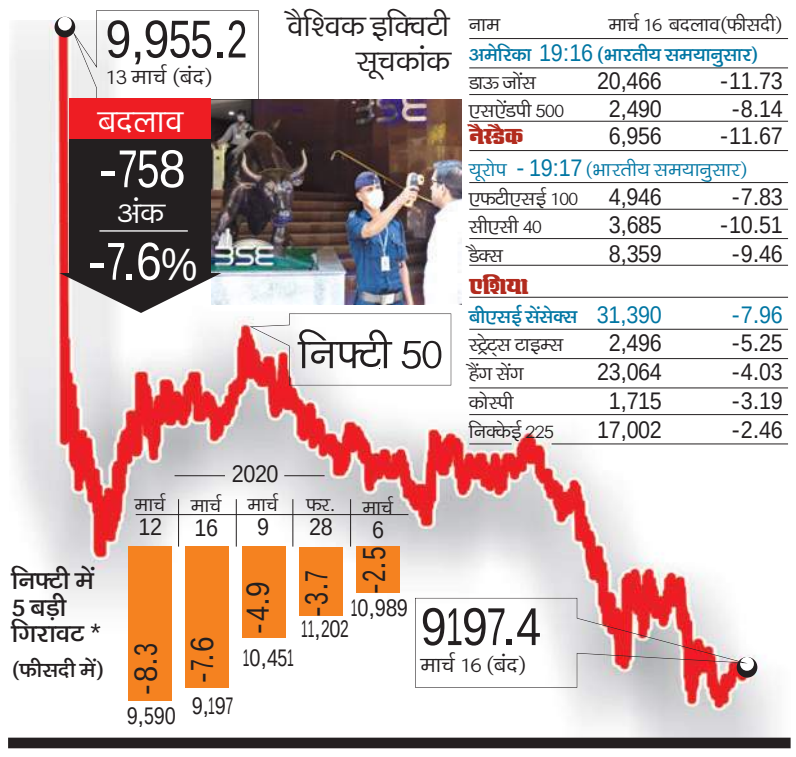

नाम	मार्च 16	बदलाव(फीसदी)
अमेरिका 19:16 (भारतीय समयानुसार)		
डाऊ जोंस	20,466	-11.73
एसऐंडपी 500	2,490	-8.14
नैस्डैक	6,956	-11.67
यूरोप - 19:17 (भारतीय समयानुसार)		
एफटीएसई 100	4,946	-7.83
सीएसी 40	3,685	-10.51
डैक्स	8,359	-9.46
एशिया		
बीएसई सेंसेक्स	31,390	-7.96
स्ट्रेट्स टाइम्स	2,496	-5.25
हैंग सेंग	23,064	-4.03
कोस्पी	1,715	-3.19
निक्केई 225	17,002	-2.46

विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय बैंक बाजार को राहत देने के लिए हरसंभव उपाय कर रहा है। बाजार इस समय इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है।

बीएनपी पारिबा के इंडिया इक्विटी रिसर्च के प्रमुख अभिराम एलेस्वरापू ने कहा, 'निवेशक विभिन्न केंद्रीय बैंकों द्वारा उठाए गए कदमों को इस तरह देख रहे हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का असर शुरुआती अनुमानों से कहीं ज्यादा भयावह होगा। केंद्रीय बैंकों के पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं।'

दुनियाभर में कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 166,000 से ऊपर पहुंच चुकी है जबकि 6,400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इटली के बाद शनिवार को स्पेन में भी पूरी तरह व्यवस्थाएं ठप हो गई। नाइकी और ऐपल ने बड़ी संख्या में अपने स्टोर बंद करने की घोषणा की है।

हॉलैंड ने कहा, 'बाजारों में स्थिरता लाने के लिए सरकार को मजबूत राजकोषीय उपायों की घोषणा करनी चाहिए। नए मामलों के बढ़ने से बाजार में उतार-चढ़ाव की स्थिति है।' अभी मुख्य सूचकांक जनवरी मध्य में अपने उच्चतम स्तर से 25 फीसदी से नीचे हैं। शुक्रवार को घरेलू बाजारों ने कारोबार के दौरान अपने न्यूनतम स्तर से 16 फीसदी की छलांग मारी थी। लेकिन यह राहत ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह पाई।

दूरसंचार कंपनियों को मिलेगी राहत!

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 16 मार्च

दूरसंचार नियामक ने उच्चतम न्यायालय में अपनी एक याचिका में कहा कि वह न्यायालय के 24 अक्टूबर के आदेश के अनुसार दूरसंचार कंपनियों से बकाया रकम वसूलना चाहता है। इसका मतलब है कि कंपनियां समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का भुगतान शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुसार करेंगी और उन्हें आदेश की तिथि के बाद बकाया रकम पर ब्याज और जुर्माने आदि का भुगतान नहीं करना होगा।

विभाग ने कहा कि कंपनियों को अगले 20 वर्षों के दौरान बकाया रकम का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी। इस बारे में याचिका का हवाला देते हुए एक सूत्र ने कहा,'बकाया रकम पर ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज शीर्ष न्यायालय के आदेश की तिथि के बाद बचने वाली बकाया रकम पर प्रभावी नहीं होगा।' हालांकि दूरसंचार विभाग ने अपनी याचिका में कहा है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस फीस एवं स्पेक्ट्रम उपयोगिता शुल्कों की बकाया रकम पर ब्याज, जुर्माने और जुर्माने पर ब्याज का भुगतान करना होगा, जो 24 अक्टूबर के आदेश के बाद प्रभावी हुआ है।

शीर्ष न्यायालय ने सरकार की याचिका पर प्रमुख कारोबार को छोड़कर अन्य गतिविधियों से प्राप्त राजस्व सालाना एजीआर में शामिल करने की बात मान ली थी। सूत्रों ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने कंपनियों के लिए भुगतान की अवधि में ढिलाई की गुजारिश की है और यह अवधि 20 वर्षों तक हो सकती है। हालांकि कुछ ऐसे लाइसेंस भी हैं, जिनकी अवधि इस समय सीमा से पहले समाप्त हो रही है। कुल मिलाकर 16 दूरसंचार कंपनियों पर एजीआर के मद में सरकार का 1.47 लाख करोड़ रुपये बकाया है।

वैश्विक बाजारों में चौतरफा गिरावट

कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत दरों में भारी कटौती के बावजूद वैश्विक बाजारों को कोई राहत नहीं मिली और उनमें गिरावट का दौर फिर से लौट आया। एशिया के बाजारों में भारी गिरावट रही और ऑस्ट्रेलिया का बेंचमार्क सूचकांक करीब 10 फीसदी गिर गया। यूरोप में लंदन का एफटीएसई 100 शुरुआती कारोबार में 6 फीसदी ढह गया जबकि फ्रांस के सीएसी 40 और जर्मनी के डीएएक्स में करीब 8 फीसदी की शुरुआती गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी बाजारों में भी भारी नुकसान की आशंका है।

चांदी 11 वर्षों के निचले स्तर पर

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) पर सोने, चांदी और कच्चे तेल के दाम आज लोअर सर्किट को छू गए। कोरोनावायरस के तेजी से फैलाव के कारण दुनियाभर के इक्विटी बाजारों में बिकवाली हुई है, जिससे मार्जिन की भरपाई के लिए सराफा, धातु और ऊर्जा समेत अन्य परिसंपत्ति वर्गों पर दबाव बढ़ा है। वैश्विक बाजारों के घटनाक्रमों का घरेलू बाजारों पर भी असर दिखा। वैश्विक बाजारों में चांदी के दाम मई 2009 के बाद सबसे नीचे आ गए हैं। पृष्ठ 6

येस के ग्राहकों की जमा सुरक्षित: दास

अनूप रॉय
मुंबई, 16 मार्च

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर शक्तिकांत दास ने येस बैंक के ग्राहकों को आश्वस्त किया कि उनकी रकम पूरी तरह सुरक्षित है। दास ने कहा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह पूरी तरह सुरक्षित है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।

आरबीआई गवर्नर ने बाजार में डॉलर की कमी दूर करने के लिए भी कदम उठाने की घोषणा की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा आनन फानन में दरें घटाने के बाद बॉन्ड पर प्राप्तियां काफी कम हो गई थीं। उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक की तर्ज पर आरबीआई भी मुख्य दरों में कटौती कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दास ने कहा कि आरबीआई के पास हालात से निपटने के कई उपाय हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि आरबीआई ने यह भी लगभग स्पष्ट कर दिया कि अप्रैल के पहले हफ्ते से पहले दरों में कटौती संभव नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार येस बैंक पर दास के बयान के बाद कहा कि इससे बाजार में और अधिक भरोसा आएगा। येस बैंक में अब एसबीआई की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हो गई है।

कुछ होटलों में भी रखेंगे 'संदिग्ध'

अनीश फडणीस और शैली सेठ मोहिले
दिल्ली/मुंबई, 16 मार्च

- दिल्ली और मुंबई के कुछ होटलों में कमरे किए गए आरक्षित
- प्रशासन ने होटलों को दिया रियायती दर पर कमरे मुहैया कराने का आदेश
- हवाईअड्डे से सटे इन होटलों में रह सकते हैं विदेश से आने वाले यात्री

घातक वायरस कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को अलग-थलग रखने के लिए हवाईअड्डों के नजदीक स्थित होटलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब 11 देशों से भारत आने वाले यात्रियों को इन होटलों में रखा जा रहा है।

महामारी पर काबू पाने के लिए अपनाए गए नए सुरक्षा मानदंडों के तहत सर्वाधिक प्रभावित 11 देशों से आने वाले यात्रियों को हवाईअड्डे से सटे होटलों में रखा जा रहा है। इनमें चीन, इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के अलावा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतर, ओमान और कुवैत से आने वाले यात्री शामिल हैं। भारत पहुंचते ही इन यात्रियों की सरकारी अस्पतालों में विधिवत जांच की जाती है और उनमें पाए जाने वाले जोखिम को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग-थलग रखने के लिए भेज दिया जाता है।

बुखार या कफ से प्रभावित यात्रियों को अलग-थलग निगरानी केंद्रों में भेजा जा रहा है जबकि मध्यम या कम जोखिम वाले लोगों को किसी सरकारी अस्पताल में अलग वार्ड में रहने के लिए भेज दिया जाता है। उनके पास बेहद रियायती दर पर नजदीकी होटल में भी अलग-थलग रहने का विकल्प है।

नई दिल्ली की जिला मजिस्ट्रेट तन्वी गर्ग ने हवाईअड्डे के पास स्थित एयरोसिटी के तीन होटलों को बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए कमरे आरक्षित रखने के आदेश रविवार को जारी किए। आइबिस, रेड बॉक्स और लेमन ट्री होटलों से कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और दिल्ली संक्रामक रोग कोविड-19 के प्रावधानों के तहत उन्हें अपने 36 कमरे आरक्षित रखने होंगे।

सोमवार को वृहन्मुंबई नगर निगम ने भी बताया कि मुंबई हवाईअड्डे के पास स्थित मिराज होटल को वायरस प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को अलग-थलग रखने के लिए केंद्र बना दिया गया है। होटल में 24 घंटे रहने के बाद उन्हें अपने घरों में अलग-थलग रहने को कहा जाएगा और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारी नियमित रूप से उनकी निगरानी करते रहेंगे। दिल्ली की एयरोसिटी में स्थित सभी होटलों के प्रतिनिधियों को स्थानीय प्रशासन ने रविवार शाम को बैठक के लिए बुलाया था। उसके बाद ही तीन होटलों को अपने कमरे निगरानी के लिए आरक्षित रखने का आदेश जारी कर दिया गया। इसी तरह की एक बैठक मुंबई के स्थानीय प्रशासन ने भी सोमवार को होटल प्रतिनिधियों के साथ की।

आइबिस ब्रांड के होटलों का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब होटल्स के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्याधिकारी जे बी सिंह ने कहा, 'सरकार से हमसे संपर्क किया था और हम जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमने इसके लिए सारी तैयारियां कर ली हैं।'

एक नज़र

फरवरी में कम हुई थोक सूचकांक आधारित महंगाई

देश में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई फरवरी में कम होकर 2.26 प्रतिशत रह गई। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फल, सब्जी, चाय, अंडे समेत दलहन, गेहूं और मक्का जैसे खाद्यान्नों के सस्ते होने से महंगाई में नरमी आई। जनवरी में थोक महंगाई दर 3.1 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष फरवरी में यह आंकड़ा 2.93 प्रतिशत था। अर्थशास्त्रियों के अनुसार कच्चा तेल और खनिजों की कीमतों में आई कमी का असर आने वाले महीनों में दिखेगा।

एसबीआई काड्र्स का शेयर पहले दिन 10 प्रतिशत नीचे

एसबीआई काड्र्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज का शेयर सोमवार को अपने निर्गम भाव की तुलना में 10 प्रतिशत नीचे बंद हुआ। देश की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी का शेयर 678 रुपये पर बंद हुआ, जो 755 रुपये की आईपीओ कीमत की तुलना में 77 रुपये या 10.2 प्रतिशत नीचे है। इस महीने के शुरू में 10,300 करोड़ रुपये के एसबीआई काड्र्स आईपीओ के दौरान शानदार मांग देखी गई थी। इसके शेयर को 26 गुना अभिदान मिला था और इसमें 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश आवेदन प्राप्त हुए थे जिससे सूचीबद्धता के दिन इसमें अच्छी तेजी की उम्मीद जताई जा रही थी। पृष्ठ 4

ऐपल पर फ्रांस ने लगाया 1.1 अरब यूरो का जुर्माना

अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनी ऐपल पर फ्रांस के प्रतिस्पर्धा नियामक ने सोमवार को 1.1 अरब यूरो (करीब 1.2 अरब डॉलर) का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया। कंपनी पर यह जुर्माना स्वतंत्र खुदरा विक्रेताओं के साथ गैर-प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए लगाया गया है। नियामक ने अपनी जांच में पाया कि ऐपल ने अपनी आर्थिक हैसियत का दुरुपयोग करते फ्रांस में स्वतंत्र खुदरा विक्रेताओं के साथ कीमत के मोर्चे पर गैर-प्रतिस्पर्धी व्यवहार किया। फ्रांस के प्रतिस्पर्धा नियामक प्राधिकरण की प्रमुख इसाबेल सिल्वा ने कहा कि यह किसी भी मामले में किसी लगाया गया सबसे भारी जुर्माना है।

20 मार्च तक हिरासत में राणा कपूर

धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार येस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत अवधि 20 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने कपूर की हिरासत छह दिन बढ़ाने की मांग की थी ताकि धनशोधन मामले में आगे की जांच हो सके और सौदे की तह तक पहुंचा जा सके। लेकिन मुंबई के सत्र न्यायालय ने सिर्फ चार दिन का समय दिया। शुरुआत में कपूर को 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था, फिर हिरासत की अवधि में विस्तार करते हुए उसे 16 मार्च तक कर लिया गया। पृष्ठ 4

17 मार्च तक कमलनाथ साबित करें बहुमत

अपने पहले निर्देश का पालन नहीं किए जाने पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने सोमवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ को पुन: एक पत्र लिखकर मंगलवार यानी 17 मार्च तक सदन में बहुमत सिद्ध करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि राज्य विधानसभा में उनके पास बहुमत नहीं है। इससे पहले सोमवार को सदन में राज्यपाल के पूर्व के निर्देश पर बहुमत साबित करने के लिए मलनाथ सरकार ने कोई पहल नहीं की।

व्यापार गोष्ठी

महामारी से निपटने को कितने तैयार हम?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरु हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या मौजूदा हालात में आरबीआई को तत्काल घटानी चाहिए दरें

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या सेबी के उपायों से बाजार को मिलेगा करार	हां	30.00%
	नहीं	70.00%

खबरों में रहे स्टॉक

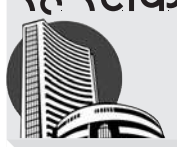

येस बैंक

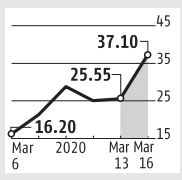

18 मार्च से इस बैंक की सभी बैंकिंग सेवाएं सुचारु होंगी

₹ 25.55 पिछला बंद भाव
₹ 37.10 आज का बंद भाव
▲ 45.21 %

इंडसइंड बैंक

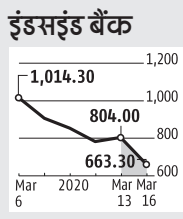

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 804.00 पिछला बंद भाव
₹ 663.30 आज का बंद भाव
▼ 17.50 %

एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स

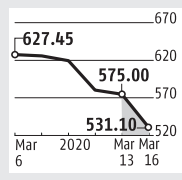

पेनलव संयंत्र के लिए यूएसएफडीए ने जारी की चार आपत्तियां

₹ 575.00 पिछला बंद भाव
₹ 531.10 आज का बंद भाव
▼ 7.63 %

पीवीआर

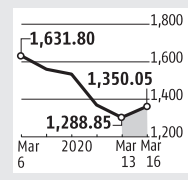

विश्लेषकों का मानना है कि लघु अवधि में सीमित होगा कोविड-19 का प्रभाव

₹ 1,288.85 पिछला बंद भाव
₹ 1350.05 आज का बंद भाव
▲ 4.75 %

वनड्रेला हॉलिडेज

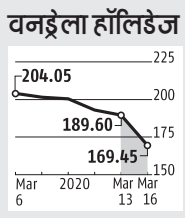

कोरोनावायरस प्रकोप के कारण हैदराबाद में एम्यूजमेंट पार्क बंद किया

₹ 189.60 पिछला बंद भाव
₹ 169.45 आज का बंद भाव
▼ 10.63 %

संक्षेप में

पार्क होटल्स को आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी

होटल कंपनी एपीजे सुरेन्द्र पार्क होटल्स को अपने अनुमानित 1,000 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। कंपनी 1,000 करोड़ रुपये का आईपीओ ला सकती है। मर्चेन्ट बैंकिंग सूत्रों के अनुसार कंपनी आईपीओ के तहत 400 करोड़ रुपये के नए शेयर तथा 600 करोड़ रुपये के प्रवर्तकों के शेयर बिक्री के लिए पेश करेगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की ताजा सूचना के अनुसार उसने ने 9 मार्च को अपनी अंतिम टिप्पणी दे दी। सेबी की इस टिप्पणी को स्वीकृति माना जाता है। कंपनी की आईपीओ के जरिये जुटाई गई राशि का उपयोग कुछ कर्ज के भुगतान और सामान्य कंपनी कामकाज में करेगी। *भाषा*

बजाज ऑटो ने उतारा बीएस-6 ऑटोरिक्शा

बजाज ऑटो ने बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाला ऑटोरिक्शा पेश किया है। कंपनी ने सोमवार को बताया कि उसने अपनी तिपहिया वाणिज्यिक वाहन श्रेणी के आरई, मैक्सिमा और मैक्सिमा कारगो मॉडल को बीएस-6 अनुरूप बनाया है। बजाज ऑटो ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने आरई, मैक्सिमा और मैक्सिमा मॉडल ब्रांड नाम के तहत कुल 14 बीएस-6 उत्पाद पेश किए हैं। इसके बाद उसके तिपहिया वाहनों की पूरी शृंखला बीएस-6 के अनुरूप हो गई है। कंपनी ने कहा कि उसके सीएनजी, एलपीजी और पेट्रोल सभी ईंधन विकल्प वाले ऑटोरिक्शा अब बीएस-6 के अनुरूप होंगे। *भाषा*

वोडा आइडिया ने किया भुगतान

सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले कंपनी जमा कराए 3,354 करोड़ रुपये

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 16 मार्च

प्रमुख दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने आज दूरसंचार विभाग को सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) के एक हिस्से के तौर पर 3,354 करोड़ रुपये के भुगतान की घोषणा की है। दूरसंचार कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई से एक दिन पहले यह रकम जमा कराई है। मामले की सुनवाई 17 मार्च को होनी है।

वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग को सौंपे एजीआर दायित्व के खुद के आकलन में कहा है कि वित्त वर्ष 2007 से वित्त वर्ष 2019 की अवधि के लिए मूलधन के रूप में कंपनी पर 6,854 करोड़ रुपये की देनदारी बनती है। इससे पहले कंपनी ने अपनी एजीआर देनदारी के लिए 17 फरवरी 2020 को 2,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया था और उसके बाद 20 फरवरी को उसने 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

वोडाफोन जीएसटी क्रेडिट के 8,000 करोड़ रुपये को बकाये में समायोजित करने और शेष रकम के भुगतान के लिए तीन साल की मोहलत देने का आग्रह किया था। उसने कहा था कि ब्याज भुगतान की अवधि 6 फीसदी की आसान ब्याज दर के साथ 15 वर्ष कर देनी चाहिए। साथ ही उसने लाइसेंस शुल्क में उल्लेखनीय कटौती और कॉल एवं डेटा के लिए न्यूनतम शुल्क निर्धारित करने की भी मांग की थी।

कंपनी को राहत मिलने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा रहा था कि वोडाफोन के ग्रुप सीईओ निक रीड ने इस महीने के आरंभ में अपने अल्पकालिक भारत यात्रा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की थी।

संचार मंत्री के साथ मुलाकात के बाद पूछ जाने पर रीड ने कोई टिप्पणी करने से इनकार किया था लेकिन दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने संकेत दिया था कि कंपनी भारत में अपना कारोबार बरकरार रखने के लिए काफी सकारात्मक थी।

दूरसंचार विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने भी कहा था, 'हम चाहते हैं कि वोडाफोन आइडिया भारत में अपना निवेश बरकरार रखे क्योंकि सरकार द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिए जाने से देश में कारोबार के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन कंपनी को अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने की जरूरत है।'

वोडाफोन पीएलसी की वोडाफोन आइडिया में 45 फीसदी हिस्सेदारी है। जबकि इस संयुक्त उद्यम में आइडिया की हिस्सेदारी 25 फीसदी है और शेष हिस्सेदारी आम शेयरधारकों की है।

दिसंबर में बिड़ला ने कहा था कि यदि वैधानिक बकाये के लिए कोई राहत नहीं दी गई तो वोडाफोन आइडिया का परिचालन बंद हो सकता है। उन्होंने कहा था, 'यदि हमें कुछ नहीं मिला तो मैं समझता हूं कि वोडाफोन आइडिया की कहानी खत्म हो जाएगी।'

सर्वोच्च न्यायालय ने 14 फरवरी को एजीआर बकाये के भुगतान के लिए समय सीमा में विस्तार के लिए भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियों की याचिका खारिज कर दी थी। शीर्ष न्यायालय ने सभी दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंस के लिए पिछले बकाये में 1.47 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। भुगतान न किए जाने की सूरत में इन कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना प्रक्रिया शुरू करने की भी धमकी दी गई थी।

एजीआर भुगतान

- कंपनी ने अपनी एजीआर देनदारी के लिए 17 फरवरी 2020 को 2,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया था
- दूरसंचार कंपनी ने 20 फरवरी को भी एजीआर बकाये के मद में 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया था

स्पेक्ट्रम लाइसेंस हो जमानती परिसंपत्ति

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 16 मार्च

आईबीए ने नियमों में बदलाव के लिए आरबीआई पर जोर देने के लिए दूरसंचार विभाग को लिखा

बैंकों के संगठन इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) ने दूरसंचार विभाग को पत्र लिख कर कहा है कि स्पेक्ट्रम लाइसेंस को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जमानती परिसंपत्ति मानने के लिए जोर दिया जाए।

आईबीए ने यह भी कहा है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के परिचालन संबंधी विभिन्न मामलों को आईबीसी के तहत अथवा उसके बाहर निपटाने के लिए समाधान की रूपरेखा तैयार की जाए। मौजूदा नियमों के तहत पूरी कंपनी के लिए समाधान प्रक्रिया शुरू की जाती है जिसमें स्पेक्ट्रम, टावर, रियल एस्टेट आदि सभी शामिल होते हैं।

आईबीए ने अपने पत्र में आईबीसी के तहत दूरसंचार क्षेत्र की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान की राह की बाधाओं को उजागर किया। पत्र में एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशंस दोनों मामलों में दिखी चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इन मामलों में खरीदार तलाशने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आईबीए ने दूरसंचार क्षेत्र के ऋण के लिए बैंकों की बढ़ती चिंता और उसके वितरीत प्रभाव का भी जिक्र किया। स्पेक्ट्रम होल्डिंग के मुद्दे पर बैंकों का कहना है कि स्पेक्ट्रम के उदारीकरण से पहले दूरसंचार विभाग, ऋणदाता और ऑपरेटर के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत ऋणदाताओं को ऑपरेटर द्वारा डिफॉल्ट की सूरत में दखल देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

हालांकि एकीकृत लाइसेंसिंग योजना के तहत केवल दूरसंचार विभाग को ही लाइसेंस को रद्द करने और उस पर रोक लगाने का अधिकार है। आईबीए ने कहा है कि आईबीसी प्रक्रिया के तहत बिक्री के समय खरीदार को इस प्रकार के स्पेक्ट्रम के हस्तांतरण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश का अभाव है।

हुंडई की नई क्रेटा के लिए हुई 14,000 बुकिंग

हुंडई मोटर इंडियाने अपनी नई क्रेटा बाजार में उतारी जिसकी 14,000 बुकिंग हो चुकी है। इसकी बुकिंग दो सप्ताह पहले शुरू हुई थी और 50 फीसदी ग्राहकों ने डीजल मॉडल का विकल्प चुना है। कंपनी ने अपने नए उत्पाद पर करीब 1,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसे घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए भारत में बनाया गया है। इसका निर्यात दो महीने बाद शुरू होगा। हुंडई ने इस बात का खुलासा करने से इनकार कर दिया कि नई क्रेटा के लिए बिक्री का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कमजोर वृहद आर्थिक परिदृश्य और कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण स्थितियां बाजार के अनुकूल नहीं हैं। हुंडई मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी एसएस किम ने कहा कि क्रेटा को 2015 में भारतीय बाजार में उतारा गया था और तबसे यह भारतीय खरीदारों के लिए एसयूवी का बेंचमार्क बन गई है। *बीएस*

बीएस4 की समय-सीमा पर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की याचिका

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 16 मार्च

वाहन विनिर्माताओं के संगठन सायम ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बीएस4 वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है। सायम ने आज एक बयान में यह जानकारी दी। बीएस4 उत्सर्जन मानदंड वाले वाहनों की बिक्री अथवा पंजीकरण के लिए अंतिम समय-सीमा 31 मार्च 2020 निर्धारित की गई थी।

हाल में कुछ राज्य सरकारों ने परिपत्र जारी कर वाहन विनिर्माताओं को निर्देश दिया था कि एक निश्चित तिथि को अथवा उसके बाद बीएस4 वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वह तिथि 31 मार्च 2020 से पहले और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2020 से अनिवार्य तौर पर केवल बीएस6 उत्सर्जन मानदंड वाले वाहनों की बिक्री करने का निर्देश दिया है।

सायम के अध्यक्ष राजन वढ़ेरा ने कहा, 'इन परिपत्रों ने ग्राहकों, डीलरों और वाहन विनिर्माताओं पर दबाव बढ़ा दिया है क्योंकि वे सभी डीलरों के पास मौजूदा बीएस4 वाहनों के स्टॉक को खपाने में लगे हैं।'

यह पहल ऐसे समय में की गई है जब वाहन विनिर्माताओं, खास तौर पर दोपहिया वाहन विनिर्माताओं को पुराने उत्सर्जन मानदंड वाले वाहनों की इन्वेंटरी को खपाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। आर्थिक मंदी के कारण उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। इसके अलावा कोविड-19 का प्रकोप बढ़ने से सरकार ने यात्रा और सामाजिक कार्यक्रम में एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी है जिससे ग्राहकों की धारणा बुरी तरह प्रभावित हुई है।

एनएसई सूचकांक से जल्द बाहर होगा येस बैंक

जस कृपलानी
मुंबई, 16 मार्च

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने इसी गुरुवार यानी 19 मार्च से एनएसई सूचकांकों से येस बैंक को बाहर करने का निर्णय लिया है। स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि इस बैंक की हालिया पुनर्गठन योजना को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। एनएसई ने येस बैंक के शेयरों के खरीद-फरोख्त पर कुछ पाबंदियां भी लगाई है। इससे पहले उसका निष्कासन 27 मार्च से प्रभावी होना था।

येस बैंक का शेयर आज काफी सुधरकर 45.2 फीसदी बढ़त के साथ बंद हुआ। लॉक-इन के बाद आपूर्ति के अभाव और शॉर्ट कवरिंग के कारण इस शेयर में तेजी आई। एडलवाइस सिक्योरिटीज के वैकल्पिक एवं मात्रात्मक अनुसंधान प्रमुख योगेश राधके ने कहा, 'लॉक-इन में 75 फीसदी शेयर हैं और इसलिए शेयरों की आपूर्ति कम है। बाजार में करीब 60 करोड़ शेयर उपलब्ध हैं और वायदा में छूट के साथ खरीद-फरोख्त की गई। हमने कुछ शॉर्ट कवरिंग भी देखी क्योंकि भविष्य के अनुबंधों को मई में निपटाया जाएगा।'

बाजार प्रतिभागियों के अनुसार, डेरिवेटिव बाजार में खरीद-फरोख्त के लिए 25 करोड़ शेयर उपलब्ध हैं।

एनएसई ने एक नोट में कहा है कि येस बैंक से संबंधित हालिया घटनाक्रमों और येस बैंक लिमिटेड पुनर्गठन योजना 2020 पर 13 मार्च 2020 को जारी राजपत्र अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए सूचकांक की रखरखाव उप समिति ने येस बैंक को निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक सूचकांकों से जल्द बाहर करने का निर्णय लिया है। येस बैंक को गुरुवार यानी 19 मार्च 2020 से प्रभावी तौर पर निफ्टी के सभी इक्विटी सूचकांकों से बाहर कर दिया जाएगा।

बाजार प्रतिभागियों के अनुसार, इस शेयर को निर्धारित तिथि से पहले ही सभी निफ्टी सूचकांकों से बाहर किए जाने से निफ्टी और निफ्टी-लिंक्ड म्युचुअल फंड से ताजा निवेश प्रवाह को रोकने में मदद मिलेगी। सरकार ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा था कि येस बैंक के नए और मौजूदा शेयरधारकों को तीन साल की लॉक-इन अवधि में 25 फीसदी से अधिक शेयरों की खरीद-बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी।

येस बैंक में 75 फीसदी निवेश के लिए तीन साल की लॉक-इन अवधि के मुद्दे पर म्युचुअल फंडों को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निर्देश का इंतजार है क्योंकि येस बैंक को सूचकांकों से बाहर करने पर उन्हें मजबूरन अपना निवेश समेटना पड़ेगा। हालांकि लॉक-इन अवधि के कारण शेयरों की खरीद-फरोख्त नहीं हो पाएगा। येस बैंक में 29 फीसदी तक 50 से अधिक सूचकांक और एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) का निवेश था।

ओएनजीसी देगी अंतरिम लाभांश

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल ऐंड नैचुलर गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) ने सोमवार को अपने शेयरधारकों के लिए 5 रुपये प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया। इस घोषणा से सरकार को कंपनी में उसकी हिस्सेदारी पर 3,950 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

ओएनजीसी ने नियामकीय सूचना में कहा है कि उसके निदेशक मंडल की सोमवार को बैठक हुई जिसमें कंपनी के प्रत्येक 5 रुपये के शेयर पर 5 रुपये का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की गई है। ओएनजीसी में सरकार की 62.78 फीसदी हिस्सेदारी है। इस हिस्सेदारी पर सरकार को 3,949 करोड़ रुपये का लाभांश और कर की प्राप्ति होगी। बंबई स्टॉक एक्सचेंज में सोमवार को ओएनजीसी का शेयर 8.73 फीसदी घटकर 60.15 रुपये पर बंद हुआ। *भाषा*

दायरा बढ़ाने पर मेकमाईट्रिप का जोर

नेहा अलावधी
नई दिल्ली, 16 मार्च

गुरुग्राम की कंपनी मेकमाईट्रिप अपने मौजूदा ऐप को बेहतर बनाने के लिए उसे नए सिरे से डिजाइन कर रही है और उसमें कई नए फीचर जोड़ रही है। कंपनी ने अपने ऐप में छुट्टियां बिताने के लिए नए गंतव्यों को भी जगह दी है। मुख्य तौर पर हवाई टिकटों और होटलों की बुकिंग करने वाले ऐप के तौर पर मेकमाईट्रिप सभी तरह की यात्रा श्रेणियों- सड़क, ट्रेन अथवा हवाई- में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर विभिन्न तरह की प्रॉपर्टी में विस्तार करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

मेकमाईट्रिप के सह-संस्थापक एवं ग्रुप सीईओ राजेश मैगो ने कहा कि ठहरने की वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कंपनी की नजर विलाओं, सर्विस अपार्टमेंटों और हॉस्टलों पर है जो विशेषतौर पर वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों पर आधारित है। फिलहाल उसके पास ऐसी 17,000 प्रॉपर्टी उपलब्ध है। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर पांच सितारा होटल पहले से ही मौजूद है और अब वह प्रीमियम एवं अल्ट्रा-प्रीमियम प्रॉपर्टी पर भी अधिक ध्यान दे रही है।

मैगो ने कहा, 'हमारा जोर मझोली श्रेणी और प्रमियम पर है। हालांकि उसमें पांच सितारा भी शामिल है लेकिन हम अल्ट्रा-लक्जरी तरह की प्रॉपर्टी पर काम कर रहे हैं।' उनके अनुसार, मेकमाईट्रिम लेनदेन सुनिश्चित करने वाली साइट है लेकिन अब वह ग्राहकों को विभिन्न गंतत्व उपलब्ध कराने के लिए भी योजना बना रही है।

कंपनी उपयोकर्ताओं द्वारा तैयार तस्वीरों और वीडियो सामग्रियों को भी शामिल करने पर काम कर रही है। इसके अलावा वह ट्रिप असिस्ट जैसे एक अन्य सुविधा पर भी काम कर रही है। यह चैटबॉट की तरह होगी जो ग्राहकों द्वारा बुकिंग किए जाने के बाद यात्रा संबंधी विभिन्न मुद्दों को निपटाने में मदद करेगी।

मेकमाईट्रिप हवाई अड्डों, शॉपिंग केंद्रों और खानपान की दुकानों के साथ भी करार करने की कोशिश कर रही है ताकि ग्राहकों को फूड ऐंड बेवरिजेस श्रेणी में इसे उपलब्ध कराया जा सके। कंपनी मलेशिया और सिंगापुर के लिए वीजा-एट योर डोर स्टेप सुविधा पहले से ही उपलब्ध करा रही है। अब वह इसमें अन्य देशों को भी जोड़ने की तैयारी कर रही है।

कोरोनावायरस का प्रभाव

आईटी कंपनियों की आय घटेगी

श्रीपाद ऑटे
मुंबई, 16 मार्च

कोरोनावायरस के लगातार प्रसार से चिंतित प्रमुख वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें घटाकर या सस्ती पूंजी मुहैया कराकर इस महामारी के आर्थिक प्रभाव को कमजोर बनाने पर जोर दिया है। जहां आरबीआई ने सोमवार को घरेलू बैंकिंग व्यवस्था में आसान नकदी के उपायों की घोषणा की, वहीं रविवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दरें घटाकर लगभग शून्य कर दीं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन उपायों से कितनी मदद मिलेगी, क्योंकि कमजोर मांग परिदृश्य का कई प्रमुख आईटी कंपनियों पर प्रभाव पड़ा है। अमेरिकी वित्तीय सेवाओं, रिटेल और ऊर्जा क्षेत्रों पर ज्यादा निर्भरता की वजह से इन कंपनियों को दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और विप्रो जैसे प्रमुख आईटी कंपनियां अपने कुल राजस्व का 21-32 प्रतिशत हिस्सा बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा) क्षेत्र से कमाती हैं और अमेरिका का उनके राजस्व में 50 प्रतिशत से ज्यादा का योगदान रहा है।

आय में 8-10 प्रतिशत कमी का अनुमान

■ बीएफएसआई, रिटेल और ऊर्जा जैसे प्रमुख ग्राहक खंडों द्वारा कम खर्च की वजह से राजस्व और मार्जिन प्रभावित हो सकता है

पिछले एक महीने में निफ्टी में 24 प्रतिशत की गिरावट के बीच निफ्टी का आईटी सूचकांक भी 25 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। आईटी क्षेत्र के लिए अनुकूल समझी जाने वाली रुपये में गिरावट के बावजूद इन शेयरों में कमजोरी आई है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में विश्लेषक अमित चंद्रा का कहना है, 'अमेरिका समेत वैश्विक रूप से बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती के नकारात्मक प्रभाव की वजह से भारतीय आईटी कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में वृद्धि सपाट बनी रह सकती है। इस वजह से वित्त वर्ष 2021 में प्रमुख आईटी कंपनियों के लिए ऊंचे एक अंक की राजस्व वृद्धि हासिल करना कठिन होगा।'

शेयरखान में शोध प्रमुख संजीव होता का कहना है, 'अमेरिका में दर कटौती से बीएफएसआई ग्राहकों का खर्च प्रभावित होगा और कोरोनावायरस के प्रभाव के बीच कुछ खास वर्टिकलों में ग्राहकों के अतिरिक्त खर्च में कमी आएगी।'

आईटी पर ग्राहकों के खर्च में कमी से भारतीय आईटी कंपनियों पर दो तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा- मौजूदा सौदों के सफल होने में विलंब होगा और नए सौदों का आकार घटेगा। मार्जिन पर भी दबाव देखा जा सकता है, क्योंकि ग्राहक अपने पैसे की अधिक वैल्यू तलाश रहे हैं। कोरोनावायरस से पहले से ही दबाव झेल रहे बीएफएसआई वर्टिकल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तिमाही आधार पर कई आईटी कंपनियों को दिसंबर 2019 तिमाही में बीएफएसआई सेगमेंट में नकारात्मक वृद्धि का सामना करना पड़ा।

बीएफएसआई ही नहीं, रिटेल सेगमेंट पर भी दबाव दिखेगा। कुछ आईटी कंपनियों के लिए रिटेल दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस वर्टिकल (राजस्व में 15-17 प्रतिशत योगदान) रहा है। कोरोनावायरस के प्रसार की वजह से अमेरिका और यूरोप में रिटेल स्टोर बंद हैं। कुछ विश्लेषकों ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से ऊर्जा खंड पर भी कुछ दबाव पड़ने की आशंका जताई है।

एसबीआई काड्र्स पहले दिन 10 प्रतिशत नीचे

निर्गम भाव की तुलना में इस शेयर में पहले दिन बड़ी गिरावट दर्ज की गई

बीएस संवाददाता
मुंबई, 16 मार्च

सेकंडरी बाजार में गिरावट के साथ एसबीआई काड्र्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज का शेयर अपने निर्गम भाव की तुलना में 10 प्रतिशत नीचे बंद हुआ। देश की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी का शेयर 678 रुपये पर बंद हुआ, जो 755 रुपये की आईपीओ कीमत की तुलना में 77 रुपये या 10.2 प्रतिशत नीचे है।

इस महीने के शुरू में 10,300 करोड़ रुपये के एसबीआई काड्र्स आईपीओ के दौरान शानदार मांग देखी गई थी। इसके शेयर को 26 गुना अभिदान मिला था और इसमें 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश आवेदन प्राप्त हुए थे जिससे सूचीबद्धता के दिन इसमें अच्छी तेजी की उम्मीद जताई जा रही थी।

हालांकि एसबीआई कार्ड आईपीओ के समय में भी कोरोनावायरस का प्रभाव बना हुआ था, लेकिन पिछले एक सप्ताह में स्थिति ज्यादा बदतर हुई है। 5 मार्च से (आईपीओ के बंद होने की तारीख) सेंसेक्स में 18 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है।

आईपीओ के समय, कई निवेशक एसबीआई काड्र्स के 30 प्रतिशत से ज्यादा तेजी पर सूचीबद्ध होने की उम्मीद जता रहे थे।

कमजोर सूचीबद्धता से अमीर निवेशक (एचएनआई) प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने इस शेयर में दांव लगाने के लिए रकम उधार भी

ली थी। निवेश बैंकरों का कहना है कि एचएनआई को 200 रुपये प्रति शेयर का नुकसान हुआ है, क्योंकि उधार ली गई रकम पर ब्याज समेत उनकी कुल खरीद लागत 870 रुपये के आसपास रही। अमीर निवेशकों ने इस आईपीओ में 80,000 करोड़ रुपये का दांव लगाया था।

शेयर एनएसई पर 755 रुपये के ऊंचे और 656 रुपये के निचले स्तरों पर पहुंचा। इसमें 4,320 करोड़ रुपये के सौदों की अदला-बदली हुई। अन्य 300 करोड़ रुपये के शेयरों का कारोबार बीएसई पर हुआ।

येस बैंक के परिदृश्य पर कई निवेशकों द्वारा उत्साह दिखाए जाने के बावजूद इस आईपीओ की सूचीबद्धता कमजोर रही। उदाहरण के लिए, मैक्वेरी ने 1,025 रुपये के कीमत लक्ष्य के साथ इस शेयर के लिए बेहतर प्रदर्शन की रेटिंग दी है। पिछले कुछ वर्षों में एसबीआई काड्र्स ने मजबूत वृद्धि दर्ज की है।

एंटनी वेस्ट ने अपना आईपीओ वापस लिया

कमजोर बाजार धारणा की वजह से पर्याप्त आवेदन नहीं मिल पाने के बाद एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल ने सोमवार को अपना आईपीओ वापस ले लिया। अपशिष्ट प्रबंधन कंपनी के 200 करोड़ रुपये के आईपीओ को सिर्फ 49 प्रतिशत अभिदान मिला। निर्गम कीमत कम होने और आखिरी तारीख एक सप्ताह तक बढ़ाए जाने के बावजूद इस आईपीओ में निवेशकों की ज्यादा दिलचस्पी देखने को नहीं मिली। कोरोनावायरस के प्रसार की वजह से बाजार में भारी बिकवाली को देखते हुए बर्गर किंग इंडिया और रोसारी बायोटेक समेत अन्य कंपनियों ने भी आईपीओ लाने की अपनी योजनाओं को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। *बीएस*

वैश्विक पैसिव फंडों और एल्गो रणनीतियों से बाजार में गिरावट

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 16 मार्च

पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में बाजार में आई बड़ी गिरावट की मुख्य वजह वैश्विक पैसिव फंडों द्वारा बिकवाली और एल्गो-आधारित रणनीतियां हो सकती हैं।

एमके ग्लोबल फाइनैंशियल सर्विसेज द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 19 फरवरी से अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा भारतीय इक्विटी में 4.6 अरब डॉलर की कुल बिकवाली में लगभग दो-तिहाई का योगदान पैसिव फंडों का रहा।

यह अनुमान 1.5 लाख करोड़ डॉलर की प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) वाले लगभग 200 एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) के अध्ययन पर आधारित है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि इस अवधि के दौरान इन ईटीएफ ने 25 अरब डॉलर की निकासी दर्ज की।

इंडेक्स फंडों और ईटीएफ ने पिछले पांच वर्षों के दौरान विकसित बाजारों में बड़ा पूंजी प्रवाह दर्ज किया है। इसलिए इन फंडों का ताजा बिकवाली में बड़ा योगदान रहा। विश्लेषकों का

मानना है कि ब्लैकरॉक, टेम्पलटन और फिडेलिटी जैसे वैश्विक फंड अपने कुल निवेश का 10-30 प्रतिशत हिस्सा पैसिव रणनीतियों के जरिये निर्धारित कर सकते हैं।

डाल्टन कैपिटल एडवाइजर्स के निदेशक यूआर भट ने कहा, 'बिकवाली दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि ईटीएफ संबंधित निवेशकों द्वारा बिक्री ऑर्डरों को पूरा करते हैं। वे मूल्यांकन आकर्षक होने की स्थिति में निचले स्तरों पर शेयरों की पुन: खरीद या अन्य शेयर खरीदने के लिए मौजूदा शेयर बेचने या नकदी का इस्तेमाल करने का निर्णय नहीं ले सकते, जैसा कि ऐक्टिव फंडों के साथ संभव है। कीमत या मूल्यांकन के संबंध में निवेश से निकलने की होड़ और खरीदारों के अभाव की वजह से कीमतों में और गिरावट आ सकती है।'

भट का कहना है कि एल्गो-आधारित स्टॉप लॉस के साथ हेज फंडों द्वारा बिकवाली से इस बाजार में भी बदलाव दिखा है। भट कहते हैं, 'स्टॉप लॉस पूरा होने पर ये फंड बिकवाली बढ़ा देते हैं।'

एल्गोरिदम ट्रेडिंग को भारत में 2009 में शुरू किया गया था और इसमें कंप्यूटर स्वत: ही पहले से निर्देशित सौदों को पूरा कर देता है। एक्सचेंज कारोबार में इस ट्रेडिंग का लगभग 40 प्रतिशत योगदान है। अमेरिका जैसे विकसित बाजारों में कुल कारोबार का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा एलगोरिदम ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है।

यूट्रेड सॉल्युशंस के संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी कुणाल नंदवानी के अनुसार, भारत में एल्गो कारोबारियों ने बाजार में उतार-चढ़ाव की वजह से पिछले एक या दो सप्ताह में कमाई की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ मामलों में एल्गो से अतीत में बाजार गिरावट को भी बढ़ावा मिला है जिसकी मुख्य वजह एल्गोरिदम का कमजोर क्रियान्वयन रहा है।

अनिल अंबानी को समन जारी

भाषा
नई दिल्ली/मुंबई, 16 मार्च

प्रवर्तन निदेशालय ने दी जानकारी

- धनशोधन की जांच के संबंध में जारी किया गया समन
- अनिल अंबानी के अलावा जी समूह के सुभाष चंद्रा और जेट के संस्थापक नरेश गोयल भी तलब
- इंडिया बुल्स के समीर गहलोत और डीएचएफएल के कपिल बधावन की भी होगी पेशी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने येस बैंक के प्रवर्तक राणा कपूर एवं अन्य के खिलाफ जारी धनशोधन जांच के संबंध में रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को समन जारी किया है। अधिकारियों ने आज बताया कि उन्हें सोमवार को निदेशालय के मुंबई कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ व्यक्तिगत आधार पर पेशी से छूट की मांग की। अधिकारियों ने कहा कि अब उन्हें 19 मार्च को बुलाया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि येस बैंक से लिए गए कर्ज में से जो खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में तब्दील हो गए, उनमें अनिल अंबानी के समूह की कंपनियां बड़े कर्जधारकों में हैं। अधिकारियों ने बताया कि अंबानी (60) ने कुछ निजी कारणों से उपस्थित होने से छूट की मांग की है, और संभव है कि उन्हें नई तारीख दे दी जाए। अनिल अंबानी की कंपनियों द्वारा येस बैंक से लिए गए कर्ज में 12,800 करोड़ रुपये एनपीए हो गए हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छह मार्च को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि अनिल अंबानी समूह, एस्सेल, आईएलएफएस, डीएचएफएल और वोडाफोन एस बैंक के बड़े कर्जदारों में शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि उन सभी बड़ी कंपनियों के प्रवर्तकों को बुलाया जाएगा, जिनके द्वारा येस बैंक से लिए गए कर्ज एनपीए हो गए हैं। धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अंबानी का बयान दर्ज होगा।

एटी-1 में सरकारी व निजी बैंकों में भेदभाव : एसऐंडपी

अभिजित लेले
मुंबई, 16 मार्च

रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड ऐंड पुअर्स ने येस बैंक के अतिरिक्त टियर-1 (एटी-1) बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने को भारत में सरकारी व निजी बैंकों द्वारा जारी किए गए उत्पाद में विभेद करना बताया है।

एजेंसी ने आज कहा कि इससे संपत्ति प्रबंधकों को नुकसान होगा और जारीकर्ताओं की पूंजी की लागत बढ़ेगी। एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग क्रेडिट एनलिस्ट दीपाली छाबड़िया ने कहा कि पूरी तरह से बट्टे खाते में डाले जाने से रिस्क प्रीमियम बढ़ सकता है, जो भारत में निवेशकों की लागत बढ़ाएगा।

येस बैंक के एटी-1 के बकाये के करीब 8,700 करोड़ रुपये को बट्टे खाते में डालने की बेलआउट योजना की जरूरत है। एटी-1 निवेशकों ने रिजर्व बैंक, येस बैंक और सरकार के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की है। मीडिया में आई रिपोर्ट से संकेत मिलते हैं कि इसके पक्षकार न्यायालय के बाहर मामले के समाधान का विकल्प तलाश रहे हैं, जिसमें एटी-1 को इक्विटी में बदलना शामिल है।

बेसल-3 फ्रेमवर्क के मुताबिक एटी-1 उत्पाद को जोखिम खत्म करने वाले उत्पाद के रूप में तैयार किया गया है। वित्तीय दबाव की स्थिति में संभव है कि इसका धारक संभवत: पुनर्भुगतान न पाए। भारत के नियमों में कहा गया है कि इस तरह के उत्पाद नुकसान को समायोजित करने के लिए हैं।

रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि येस बैंक के एटी-1 को स्थायी रूप से बट्टे खाते में डालने का रिजर्व बैंक का फैसला एजेंसी के विचार के अनुरूप था, जिसमें प्रावधान है कि इस तरह के उत्पाद निजी क्षेत्र के बैंक को होने वाले नुकसान के समायोजन के लिए होंगे, न कि सार्वजनिक क्षेत्र के। भारतीय बैंकों के एटी-1 में यह सुविधा मुहैया कराई गई है कि भारत सरकार को जारीकर्ता द्वारा प्रवर्तक के रूप में कारोबार के सामान्य प्रक्रिया के तहत डाली गई कोई भी पूंजी गैर व्यवहार्यता ट्रिगर के रूप में संभव है कि न लगाया गया हो। इससे यह निकलकर आता है कि बैंक की मालिक सरकार है, ऐसे में उसे बैंक में पूंजी डालने का अधिकार है।

ग्राहकों को बुधवार से सभी सेवाएं

संकटग्रस्त येस बैंक के ग्राहक बुधवार शाम से बैंक की सभी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस दिन बैंक के कामकाज पर लगाई गई रोक को उठा लिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 मार्च को यस बैंक के कामकाज पर पाबंदी लगा दी थी। बैंक के ग्राहकों के लिए 3 अप्रैल तक खाते से 50 हजार रुपए तक की निकासी सीमा तय कर दी गई थी। बहरहाल, शनिवार को जारी अधिसूचना में सरकार ने कहा कि बैंक पर लगी इस रोक को 18 मार्च शाम छह बजे उठा लिया जाएगा। येस बैंक ने ट्वीट जारी कर कहा है, 'हम बुधवार 18 मार्च 2020 को शाम छह बजे से अपनी सभी बैंकिंग सेवाओं को शुरू कर देंगे। बैंकिंग सेवाएं शुरू होने के बाद 19 मार्च 2020 को आप हमारी देशभर में फैली 1,132 शाखाओं में से किसी भी शाखा में जा सकते हैं और हमारी तमाम सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।' इसमें कहा गया है, 'आप हमारी सभी डिजिटल सेवाओं और प्लेटफार्म को प्राप्त कर सकेंगे।' सरकार ने शनिवार को संकट में फंसे येस बैंक को उबारने के लिए पुनर्गठलन योजना को अधिसूचित कर दिया था। सरकार ने हा कि यस बैंक के कामकाज पर लगी रोक को 18 मार्च शाम छह बजे उठा लिया जाएगा जबकि इससे पहले 3 अप्रैल की तिथि दी गई थी। *भाषा*

20 मार्च तक हिरासत में कपूर

सुब्रत पांडा
मुंबई, 16 मार्च

मुंबई के सत्र न्यायालय ने आज धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार येस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दी गई हिरासत की अवधि सोमवार को 20 मार्च तक के लिए बढ़ा दी। ईडी ने कपूर की हिरासत 6 दिन बढ़ाने की मांग की थी, जिससे धनशोधन मामले में आगे की जांच हो सके और सौदे की तह तक पहुंचा जा सके। बहरहाल न्यायालय ने सिर्फ 4 दिन की हिरासत अवधि दी है।

जांच के दौरान एजेंसी ने पाया कि मैक स्टार मार्केटिंग को 202 करोड़ रुपये का कर्ज जारी किया गया था, जो एचडीआईएल के प्रवर्तकों सारंग वधावन और राकेश वधावन व पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन वरयाम सिंह व डे शॉ ग्रुप का संयुक्त उद्यम है। पहले तीन की हिस्सेदारी सिर्फ 16.64 प्रतिशत है, जबकि डे शॉ की बहुलांश हिस्सेदारी है। ईडी ने पाया कि मैक स्टार मार्केटिंग को दिए गए 202 करोड़ रुपये कर्ज का इस्तेमाल एचडीआईएल ने पहले के कर्ज का भुगतान करने में किया। बहरहाल इस इकाई को कार्यालय की इमारत के नवीकरण के लिए यह धन जारी किया गया था। जांच एजेंसी ने न्यायालय में आरोप लगाया कि कर्ज दिए जाने के 2 साल पहले यह इमारत बनी थी और इसकी कुल कीमत 100 करोड़ रुपये थी। साथ ही ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि यह कर्ज संयुक्त उद्यम के बहुलांश हिस्सेदारों की सहमति के बगैर लिया गया था।

जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि राणा कपूर के एचडीआईएल के प्रवर्तकों के साथ गहरे संबंध हैं और मैक स्टार को कर्ज की मंजूरी डे शॉ समूह की मंजूरी या उनकी जानकारी के बगैर की गई।

थोक महंगाई तीन माह के न्यूनतम स्तर पर

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 16 मार्च

उपभोक्ता मूल्य की तर्ज पर ही थोक मूल्य पर आधारित महंगाई भी फरवरी में कम होकर तीन महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। यह फरवरी में 2.26 फीसदी पर आ गई जो उससे पिछले महीने 3.10 फीसदी रही थी। ऐसा खाद्य वस्तुओं, पेट्रोल और डीजल की कीमत वृद्धि की दर में कमी आने के कारण हुआ।

पिछले हफ्ते जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर 68 महीनों के उच्चतम स्तर 7.59 फीसदी से घटकर 6.58 फीसदी हो गई। विनिर्मित वस्तुओं में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित दर महंगाई में इजाफा हुआ लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कोरोनावायरस के प्रभाव के कारण मांग पर असर पड़ने से आगामी महीनों में इसमें कमी आएगी। साथ ही, यदि प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं की बात करें तो बाकी विनिर्मित वस्तुओं की कीमत में कमी आना जारी रहेगा।

फरवरी महीने में खाद्य महंगाई उससे पिछले महीने के 11.51 फीसदी से कम होकर 7.79 फीसदी होने के बावजूद सब्जियों के भाव में तेजी बरकरार रही। फरवरी में सब्जियों में महंगाई 60.73 फीसदी रही हालांकि यह उसके पिछले महीने के 87.84 फीसदी से कम रही। सब्जियों में फरवरी में प्याज की कीमतें 162.30 फीसदी बढ़ी हालांकि उसके पिछले महीने इसमें 293.37 फीसदी की वृद्धि हुई थी। फरवरी में टमाटर के दाम में भी 60.73 फीसदी का इजाफा हुआ जो उससे पिछले महीने की 87.84 फीसदी की बढ़ोतरी से कम है।

गैर-खाद्य श्रेणी में प्रमुख वस्तुओं (अप्रसंस्कृत) में फरवरी महीने में खनिजों की महंगाई दर कम होकर 2.50 फीसदी रही जो उससे पिछले महीने 4.32 फीसदी रही थी। फरवरी में ईंधन और बिजली की महंगाई दर में मामूली कमी आई और यह 3.38 फीसदी रही जो उससे पिछले महीने 3.42 फीसदी रही थी। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने से डीजल और पेट्रोल की कीमत वृद्धि में भारी कमी आई। ईंधन और बिजली श्रेणी में मुख्य तौर पर तरल पेट्रोलियम गैस के कारण महंगाई में इजाफा हुआ। इस दौरान एलपीजी की महंगाई दर 1.78 फीसदी से उछलकर 21.85 फीसदी हो गई। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, 'फरवरी महीने में डब्ल्यूपीआई में भारी गिरावट का प्रमुख कारण खाद्य वस्तुओं के साथ साथ कच्चे तेल और खनिजों के दामों में कमी आना है।'

गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को मिला पहला सदस्य

श्रेया जय
नई दिल्ली, 16 मार्च

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) के गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को मणिकर्ण पावर लिमिटेड (एमपीएल) के रूप में पहला सदस्य मिल गया है। इंडियन गैस एक्सचेंज (आईजीएक्स) नाम का यह प्लेटफॉर्म भारत का पहला गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज होगा।

आईजीएक्स दहेज, हजीरा और काकीनाडा में हाजिर पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश करेगा। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) दाहेज में एलएनजी टर्मिनल का परिचालन करता है, वहीं शेल हजीरा स्थित टर्मिनल का परिचालन करता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन से उत्पादित प्राकृतिक गैस का केंद्र काकीनाडा है।

इस साल फरवरी में आईजीएक्स ने सदस्यता अभियान शुरू किया था। एमपीएल पहले से ही आईईएक्स का ट्रेडिंग सदस्य है, जिसने सबसे पहले आईजीएक्स के साथ समझौता किया है।

एमपीएल अंतर राज्यीय ट्रेडिंग लाइसेंस धारक है और वह आईईएक्स का ट्रेडिंग सदस्य है। साथ ही वह पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) का ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य है। इसकी स्थापना 2008 में नवजीत सिंह कालसी और जसप्रीत सिंह कालसी ने की थी। कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है और इसके कार्यालय दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु, हैदराबाद, चेन्नई, वडोदरा और अहमदाबाद में हैं।

आईईएक्स और पीएक्सआईएल पर बिजली की खरीद के लिए एमपीएल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, बिजली के द्विपक्षीय कारोबार में सहायता और दस्तावेदीकरण की सुविधा मुहैया कराती है।

बीएस सूडोकू 3690 | परिणाम संख्या 3689

		4						
	1		8		6		9	
				5		7		8
6					5		7	
4			1	6	8			3
	5		4					1
9		5		1				
	4		2		9		6	
						9		

1	4	6	2	7	3	9	8	5
8	9	3	4	5	1	2	6	7
2	5	7	9	8	6	1	4	3
3	1	8	6	9	4	7	5	2
5	7	9	3	2	8	4	1	6
6	2	4	7	1	5	3	9	8
7	3	5	1	6	9	8	2	4
9	6	2	8	4	7	5	3	1
4	8	1	5	3	2	6	7	9

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत आसान ★☆☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2030/2040, जौ 1825/1850, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2150/2200, सरसों 3400/3500, तिल सफेद 8600/8800, सोया (टीन) 1440/1450, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1350/1400,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2040/2050, गेहूं शरबती 2825/2925, चावल शरबती सेला 3400/3450, स्टीम 3750/3800, लालमती 2900/2950, चावल (सोना) 2600/2650,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1342, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1420, फ्लैक 1365, डीएमओ 980, टरपीन लैस बोल्ड 1425

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1080/1120, खुरपा 980/985,चाकू 1020/1090, रसकट 940/950, शक्कर 1060/1100, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3265, सिहोरा 3140, बुंदकी 3150, बुढ़ाना 3180,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3450/3500, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1040/1050, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 3900, खल: सरसों 2100/2200, बिनौला 2150/2250, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 4600/4700, गेहूं (मिल) 2100/2110, मक्की 1700/1750, बाजरा 1550/1600, जौ 1775/1800, ग्वार लूज 3400/3450, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 3990/4000,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 1900/2000, ग्वार 3200/3250, जौ 1840/1840,

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 3450/3500, ग्वारगम 5500/5600, बाजरा (गुजरात) 1700/1750, बाजरा (जयपुर) 1700/1725, चना 3950/4100, काबली चना 4700/4900, मूंग 7100/7400,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)94, राइसब्रान (अखाद्य) 91, खल सरसों 1950, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 850, लाल 850, कंटीन्यूअस 900,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 9000/9200, अरहर दाल 7400/8000, उड़द साबुत 7100/8000, उड़द धोया 8500/9000, छिलका 8200/8600, दाल मसूर 6000/6200, चनादाल 5000/5100,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 5300/5400, सेला 4800/4900, शरबती साधारण सेला 3300/3400, शरबती स्टीम 3700/3750,चावल 1509 सेला 4300/4400, धान: शरबती 1850/1900,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 3970/4020, हरियाणा 3950/3970, राजस्थान 3930/3980, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2150/2300, सरसों खल 1990/2000,

फाजिल्का
(जीएसटी अतिरिक्त): धान (1509) 2400/2450, धान मोटा 1550/1575, चावल कच्चा (आईआर-8)2200/2300, चावल सेला (आईआर-8) 2200/2250, चावल कच्चा (पीआर-11) 2500/2600,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2060/2080, चावल परमल कच्चा 2300/2325, से ला 2225/2260, मक्की यूपी 1750/1775, दाल उड़द छिलका 8800/10000, चना देशी 4650/4700, दाल चना 5000/5100, काबली चना 5000/6000, राजमां चित्रा पुणे 7600/8600, गोला 15000/16500

करनाल
गेहूं दड़ा 2050/2060, बासमती चावल 5400/5600, धान 1121 नं. 2600/2650, पूसा 1509 धान 2300/2400, शरबती धान 1900/1925, सेला (1509 नं.) चावल 4300/4400, स्टीम 5300/5400,

हिसार
ग्वार 3250/3300, जौ 1840/1850, सरसों 3650/3700, मूंग 7000/7100, गेहूं 2040/2050,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2130, आटा (प्रति 44 किलो) 975/1000, मैदा 1100/1110, देशी घी (एक ली/जार) 308/470, रिफाइंड (टीन) 1310/1350,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 3750/3800, खल बिनौला मोटी 2100/2300, बिनौला 2500/3100, सरसों तेल 8150/8200, गेहूं 2000/2100, ग्वार 3150/3200, बाजरा 1575/1600 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 25

तैयारी का वक्त

दुनिया भर के देशों में नोवल कोरोनावायरस की महामारी का विकास कमोबेश एक ही ढर्रे पर हुआ है। इसकी वृद्धि एकदम स्पष्ट रही है और गंभीर बीमारों की तादाद कभी न कभी इतनी ज्यादा हो गई कि स्वास्थ्य क्षेत्र का सामान्य बुनियादी ढांचा इसके कारण चरमराने लगा। अलग-अलग देशों में इसका रुझान भिन्न-भिन्न कारकों से अलग रहा है: सामाजिक स्तर पर लोगों का दूरी बरतना, पीड़ितों को अलग-थलग करना, ये प्रतिबंध बीमारी के किस चरण में लगाए गए, कितने परीक्षण किए गए और इस बीमारी के किस चरण में किए गए, उन संभावित पीड़ितों की पहचान कितने सटीक तरीके से की गई जिनमें अब तक बीमारी के लक्षण सामने नहीं आए हैं और आखिर में यह कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली इसका प्रबंधन करने में किस हद तक सक्षम है।

सरकार ने अब तक कोरोनावायरस पर नियंत्रण करने को लेकर समझदारी भरे कदम उठाए हैं लेकिन आने वाले सप्ताह में इसकी तीव्रता बढ़ सकती है और तब कहीं अधिक व्यापक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी। देश में ज्यादातर जगह कोरोनावायरस का प्रसार प्रारंभिक स्तर पर है। कुछ जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं लेकिन अयोध्या में रामनवमी के त्योहार जैसे भारी भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम अभी भी होने निर्धारित हैं। सरकार को जल्द से जल्द यह तय करना चाहिए कि इसे लेकर हमारी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या होगी? भारत को कोरोनावायरस संबंधी जांच को व्यापक स्वरूप देना चाहिए। हॉन्गकॉन्ग, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे जिन देशों ने भी अपनी आबादी में इस वायरस का प्रसार धीमा करने में सफलता हासिल की है, उन सभी ने इसकी गहन जांच की व्यवस्था की। ऐसा करने से उनको लोगों को लक्षित करने में आसानी हुई जो बड़ी आबादी में वायरस फैला सकते थे। गत सप्ताह के अंत तक भारत में करीब 6,000 लोगों की जांच की जा चुकी थी। मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक जांच केवल तभी की जा रही है जब उन लोगों में बीमारी के लक्षण नजर आएं जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों या बहुत जोखिम वाले इलाके में रहते हों। यह मानक कुछ ज्यादा ही सख्त है। खासकर तब जबकि टेस्ट किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और सरकार के मुताबिक उनका उत्पादन कम कर दिया गया है।

इसके अलावा अगले कुछ सप्ताह में नहीं तो बाद के दिनों में (यदि पैटर्न सन 1918-19 के नोवल इन्फ्लूएंजा जैसा हुआ) देश की आबादी के बड़े हिस्से में नोवल कोरोनावायरस फैल सकता है। भविष्य में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उससे निपटने की क्या तैयारी है? अन्य देशों का अनुभव हमारे लिए दिशानिर्देश का काम कर सकता है: लोगों को अलग-थलग करना, विस्तारित और विशिष्ट गहन चिकित्सा इकाई स्थापित करना आदि। वेंटिलेटर और मास्क की आवश्यकता होगी। साथ ही ऐसे स्वास्थ्य सुविधा प्रदाताओं की आवश्यकता होगी जो श्वसन प्रणाली में नलिका लगाने में दक्ष हों। देश में इस महामारी का देर से विस्तार हमें तैयारी का अवसर देता है। यह आश्वस्त होने का अवसर नहीं है।

हालांकि यह मुख्य तौर पर जन स्वास्थ्य की समस्या है और इससे वैसे ही निपटा जाना चाहिए लेकिन इससे निपटने की तैयारी में अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अधिकारियों को इस अवधि में उत्पादन में गिरावट को लेकर तैयारी रखनी होगी। इस दौरान समुचित और लक्षित कदम उठाने होंगे। समग्र प्रोत्साहन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह नकारात्मक भी साबित हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा और रुपये की मात्रा बढ़ाकर अपनी तरफ से सही कदम उठाया है।

अजय मोहंती

बंदरगाह सुधार में सरकार का अगला बड़ा कदम

मंत्रिमंडल ने मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल, 2020 को मंजूरी दे दी है जिससे सरकार के स्वामित्व वाले प्रमुख बंदरगाहों में नई जान आएगी। बता रहे हैं विनायक चटर्जी

देश की अर्थव्यवस्था में बंदरगाहों की बड़ी अहमियत है। इसके बावजूद देश में जितनी भी सरकारें बनी हैं, सभी ने सरकारी स्वामित्व वाले बंदरगाहों के लिए नीतिगत सुधारों की दिशा में बहुत कम ध्यान दिया है। यह तथ्य हमेशा अचंभित करता रहा है। सड़क, दूरसंचार, विद्युत, नागरिक उड्डयन जैसे सभी अन्य क्षेत्रों में सुधार देखने को मिले हैं या कम से कम उनमें सुधार की दिशा में गंभीर प्रयास किए गए हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से बंदरगाह क्षेत्र पर कम ध्यान दिया गया है।

यहां तक कि आज भी तथाकथित 'प्रमुख बंदरगाहों' को 1960 के दशक में बनी शुल्क एवं नीतिगत प्रणाली का पालन करना पड़ रहा है। देश के समुद्री मालवहन में करीब 55 फीसदी हिस्सेदारी इनमें से 12 की है। इन बंदरगाहों का शुल्क एक केंद्रीय प्राधिकरण- द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स (टेंप) तय कर रहा है। अन्य बहुत से परिचालन और वाणिज्यिक मामलों का नियंत्रण भी टेंप के हाथों में है। यह तो वैसे ही है मानो दूरसंचार मंत्रालय दिल्ली से आदेश जारी कर देश भर में फोन शुल्क दरें तय करे या विद्युत मंत्रालय देश भर में सभी विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए बिजली की दरें तय करे।

इसके नतीजतन कारोबार का एक बड़ा हिस्सा उन 'गैर-प्रमुख' या 'निजी' बंदरगाहों के पास चला गया है, जिनका एक ज्यादा उदार व्यवस्था के तहत परिचालन होता है और वे राज्य सरकारों के नियंत्रण में आते हैं।

केयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक माल की कुल आवाजाही में गैर-प्रमुख बंदरगाहों का हिस्सा वर्ष 2016 में बढ़कर 43 फीसदी हो गया, जो 1981 में 10 फीसदी था। मुंद्रा, काकीनाडा और पीपावाव जैसे ऐसे बंदरगाह न केवल परिचालन के लिहाज से ज्यादा कुशल हैं बल्कि इन्होंने माल की सुगम आवाजाही के लिए देश के भीतरी हिस्से से बेहतर संपर्क विकसित किया है।

गुजरात के गैर-प्रमुख बंदरगाह पीपावाव ने सुगम परिवहन के लिए देश के भीतरी हिस्सों से बेहतर संपर्क विकसित किया है। हालांकि प्रमुख बंदरगाहों में निजी क्षेत्र माल की आवाजाही को संभालने जैसे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। लेकिन ड्रेजिंग (बड़े जहाजों की आवाजाही को संभव बनाने के लिए बंदरगाह की गहराई बढ़ाने) और नए टर्मिनल बनाने में निवेश के जरिये निजी क्षेत्र की भागीदारी और बढ़ाने की जरूरत है।

सागरमाला परियोजना 2015 में शुरू हुई। इसका मकसद बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाना, बंदरगाहों की परिचालन कुशलता और देश के भीतरी क्षेत्रों से संपर्क सुधारना है ताकि माल का सुगमता से परिवहन हो सके। अब तक 125 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिन पर 31,000 करोड़ रुपये की लागत आई है। इन परियोजनाओं में से ज्यादातर (22,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं) बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए थीं।

बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे में निवेश के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगला तार्किक और अहम कदम उठाया है ताकि बंदरगाह नए बुनियादी ढांचे- परिचालन नीति सुधारों का फायदा उठा सकें। मंत्रिमंडल ने 12 फरवरी को एक विधेयक- द मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2020 को मंजूरी दे दी। इसका मकसद प्रमुख बंदरगाहों के प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव करना है। यह विधेयक 1963 के अधिनियम की जगह लेगा। इसलिए टेंप का दौर खत्म होने का जा रहा है, जिसकी अब तक सरकारी बंदरगाह प्रणाली पर मजबूत पकड़ थी।

दरअसल ऐसा पहला कदम 2016 में उठाया गया था, लेकिन यह विधेयक पारित नहीं हो पाया क्योंकि पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले संसद को स्थगित कर दिया गया। इस वजह से विधेयक रद्द हो गया। हालांकि हाल में मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर विधेयक के सभी ब्योरों का पता नहीं चला है, लेकिन यह 2016 के विधेयक की तर्ज पर होने के आसार हैं।

वर्ष 2016 के विधेयक में प्रमुख बंदरगाहों को ज्यादा स्वायत्तता दी गई थी। इसमें खुद ही शुल्क तय करने का अधिकार भी शामिल है। शुल्क में स्वायत्तता के अलावा 2016 के विधेयक में बंदरगाहों के बोर्डों को केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से धन (आरक्षित पूंजी के 50 फीसदी तक) जुटाने की मंजूरी दी गई थी। इसमें बंदरगाह और निजी क्षेत्र के ठेकेदारों के बीच पीपीपी परियोजनाओं को लेकर विवाद के समाधान के लिए केंद्रीकृत मध्यस्थता बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। अगर इन उपायों को ताजा विधेयक में शामिल किया गया है तो इनसे प्रमुख बंदरगाह निजी क्षेत्र के लिए निवेश और सेवा प्रदाताओं के रूप में ज्यादा आकर्षक बन जाएंगे। इस समय प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग की सेवाएं देने वाले निजी ऑपरेटरों को टेंप को अपने शुल्क का भुगतान करना होगा। यह साफ तौर पर एक अच्छा नतीजा नहीं है।

अगर पिछले कुछ वर्षों में हुए निवेश का फायदा उठाना है तो इन सुधारों को अमलीजामा पहनाना होगा। केयर की रिपोर्ट में कहा गया कि बंदरगाहों के लिए ज्यादा उदार प्रणाली के सकारात्मक असर गुजरात में सबसे बेहतर दिखते हैं, जो व्यापार और विकास के बंदरगाह आधारित मॉडल में अगुआ था। गुजरात मैरिटाइम बोर्ड राज्य में 41 गैर-प्रमुख बंदरगाहों का प्रशासनिक कामकाज संभालता है। इन बंदरगाहों का देश में गैर-प्रमुख बंदरगाहों के जरिये होने वाली माल की कुल आवाजाही में 70 फीसदी हिस्सेदारी (वर्ष 2017 में) है। गुजरात की वृद्धि दर बढ़ने में बंदरगाह बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स की अहम भूमिका रही है। गुजरात की वृद्धि 1980 के दशक में पांच फीसदी से थोड़ी अधिक थी, जो 1990 के दशक में 8 फीसदी से ऊपर पहुंच गई।

जहाजरानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। इनमें सागरमाला परियोजना से लेकर जलमार्ग के जरिये माल ढुलाई को प्रोत्साहन देने के लिए करों में बदलाव, बंदरगाह आधारित सेज का विकास और मेगा पोर्ट आदि शामिल हैं। पोर्ट अथॉरिटी बिल को संसद की मंजूरी मिलने से एक खाई पट जाएगी।

(लेखक फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन हैं।)

प्रवर्तन की कार्रवाई के डर से कंपनी सुसंचालन पर असर

कंपनी जगत राहत की सांस ले रहा है। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में एक अहम कदम उठाते हुए एक मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की। इसमें कहा गया है कि कंपनी कानून का पालन नहीं करने पर स्वतंत्र निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ नियमित रूप से कानूनी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।

इस परिपत्र को ऐसे लोगों के खिलाफ दायर मुकदमों या शुरू की गई मुकदमे की कार्यवाही पर 'स्पष्टीकरण' बताया गया। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कंपनी की गलतियों के लिए उसके प्रबंधन में अहम पद पर बैठे व्यक्ति और दैनिक कामकाज से जुड़े पूर्णकालिक निदेशकों को उत्तरदायी होना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ भी नया नहीं है बल्कि यह 1990 के दशक से ही कानून का हिस्सा था और इसे 2013 में बनाए गए नए कंपनी कानून में भी इसे कूटबद्ध किया गया था।

आखिर कानून के स्पष्ट होने के बावजूद भी इस तरह के स्पष्टीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। साफ है कि प्रवर्तन की व्यवस्था में खामी है। इस स्पष्टीकरण में वही बात कही गई है जो जुलाई 2011 में मास्टर सर्कुलर में कही गई थी। 2011 के मास्टर सर्कुलर में नवंबर 1998 में जारी इस स्पष्टीकरण पर जोर दिया गया था कि किसी कंपनी की गलतियों की सजा उसके प्रबंधन में शामिल अधिकारियों को मिलनी चाहिए और अगर प्रबंधन में कोई तय अधिकारी नहीं है, तो उसी स्थिति में निदेशकों का रुख किया जाना चाहिए।

बीच के नौ वर्षों के दौरान इन सिद्धांतों को संसद द्वारा बनाए गए कानून में कूटबद्ध किया गया लेकिन इससे कोई फर्क पैदा नहीं हुआ। यही असली कहानी है। प्रवर्तन के उचित कार्यान्वयन का मतलब है कि गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और बेगुनाहों को बेमतलब में परेशान न किया जाए। जब किसी बेगुनाह को आरोपी बनाया जाता है तो इससे समय और संसाधनों पर बिना वजह दबाव बढ़ता है। प्रवर्तन कार्रवाई की आशंका से गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन कंपनियों के बोर्ड में निदेशक बनने से कतराते हैं। इससे कंपनियों के कामकाज में गुणवत्ता लाने का व्यापक उद्देश्य प्रभावित होता है।

बाअदब

सोमशेखर सुंदरेशन

किसी कंपनी में कुछ भी गलत होता है तो राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां नियमित रूप से उसके सभी निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। ऐसे निदेशकों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के फैसलों से अदालतें पटी पड़ी हैं।

कंपनी कानून में लंबे समय से गलती करने वाले अधिकारी की अवधारणा रही है। यह ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी पहचान बोर्ड एक ऐसे शख्स के रूप में करता है जो कंपनी के कामकाज और नियमों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होती है। फिर भी कंपनी कानून का पालन कराने वाले अधिकारी और दूसरी एजेंसियां नियमित तौर पर निदेशकों पर कार्रवाई करती हैं।

2011 के मास्टर सर्कुलर में यह सुनिश्चित करने के लिए कि निदेशक के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं, बोर्ड की प्रक्रियाओं के बारे में उसकी जानकारी की जांच की अवधारणा पेश की थी। कंपनी कानून, 2013 की धारा 149 (12) में इसे जोड़ा गया था। किसी कंपनी के बोर्ड की बैठक में जो कुछ रखा जाता है, उसके लिए निदेशक अनिवार्य रूप से प्रबंधन पर निर्भर होता है। बोर्ड को प्रबंधन पर भरोसा करना होता है और वह प्रबंधन और अहम पद पर बैठे शख्स के हर फैसले को शक की निगाह से नहीं देख सकता है। अगर किसी कंपनी का बोर्ड प्रबंधन के हर फैसले पर उंगली उठाएगा और इस प्रक्रिया में शीर्ष नेतृत्व को कमजोर करेगा, तो फिर कंपनी काम नहीं कर पाएगी। इसी तरह सूचीबद्ध कंपनियों के संचालन के लिए पूंजी बाजार नियामक द्वारा बनाए गए नियमों में भी यही सिद्धांत अपनाया गया है। फिर भी आए दिन निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई की घटनाएं होती रहती हैं।

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को समझा है और स्पष्टीकरण जारी किया है। लेकिन इस बारे में जागरूकता पैदा करना और दूसरी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ क्षमता का निर्माण भी जरूरी है। किसी कंपनी में कुछ भी गलत होता है तो राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां नियमित रूप से उसके सभी निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। ऐसे निदेशकों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के फैसलों से अदालतें पटी पड़ी हैं।

साथ ही निदेशकों को जनहित याचिकाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। कई निदेशकों को अपनी परिसंपत्तियां घोषित करनी पड़ी हैं और लंबित जांच के कारण उनकी संपत्तियां सील हो गई हैं। इस महीने आए स्पष्टीकरण में कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों से आंतरिक जांच और उचित निर्देश के लंबित मामलों की भी जानकारी देने को कहा गया है। नियामकों और प्रवर्तन एजेंसियों को कंपनी मामलों के मंत्रालय की परिधि से बाहर निकालना अगला लक्ष्य होना चाहिए।

(लेखक अधिवक्ता एवं स्वतंत्र परामर्शदाता हैं।)

कानाफूसी

सबका स्वागत

जब से राष्ट्रीय जनता दल ने अमरेंद्र धारी सिंह को राज्य सभा का टिकट दिया है तब से पार्टी नेता अपने मुख्य मतदाता वर्ग यानी मुस्लिमों और यादवों को इसका कारण समझा रहे हैं। कई नेता जहां शुरुआत में इस घोषणा से चकित नजर आए, वहीं कहा जा रहा है कि पार्टी के मुखिया लालू प्रसाद ने उच्च जाति के लोगों, खासकर भूमिहारों को लुभाने के लिए जानबूझकर यह कदम उठाया है। भूमिहार प्रदेश में मजबूत हैसियत वाले हैं और उन्हें राजग समर्थक माना जाता है। लालू प्रसाद के छोटे बेटे और पार्टी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने सिंह के नामांकन को उन आलोचकों को करारा जवाब बताया है जो कहते थे कि पार्टी केवल मुस्लिमों और यादवों के हित का ध्यान रखती है। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक न्याय के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता और पिछड़े वर्ग, आर्थिक कमजोरों और दलितों के प्रति प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आएगी।

मुसीबत में साथ

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव इन दिनों साथ नजर नहीं आते लेकिन कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए साफ-सफाई का संदेश देने दोनों नेता एक साथ नजर आए। बड़े भाई तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी के चेहरे पर मास्क बांधा और उन्हें हैंड सैनिटाइजर की एक बोतल भेंट की। उन्होंने ऐसा कोरोनावायरस की महामारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के क्रम में किया। दोनों भाइयों में टकराव जगजाहिर है और पिछले कुछ समय में दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे लेकिन दोनों ने अपनी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर मास्क के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव का कद अपने बड़े भाई से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने राज्य के लोगों से अपील की कि वे सतर्क रहें, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश का पालन करें।

आपका पक्ष

नकदी रहित व्यवस्था से देश का विकास

कैशलेस भारत एक ऐसी मुहिम है जिसके द्वारा भारत सरकार नकदी आधारित अर्थव्यवस्था को डिजिटल साधनों के द्वारा नकदी रहित बनाने की दिशा में अग्रसर है। इस प्रकार सरकार देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत है। भारत जैसे विशाल देश में जहां एक बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने को मजबूर है, वहां कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने में कठिनाई आना स्वाभाविक है, लेकिन इस दिशा में प्रयास शुरू करना जरूरी था। आज डिजिटल माध्यम से मौद्रिक लेनदेन के प्रति लोगों की मानसिकता में एक बड़ा परिवर्तन आया है। लोग जान गए हैं कि डिजिटल माध्यम भी सुरक्षित, आसान, सुविधाजनक एवं पारदर्शी है और नकदी रहित भारत में काले धन या नकली नोटों की अब कोई गुंजाइश नहीं है। डिजिटल लेनदेन खर्च का हिसाब आसानी से लगाने की सुविधा प्रदान करता है। बिना नकदी के लेनदेन की जांच भी आसानी से की जा सकती है इसलिए इन पर आवश्यक करों का भुगतान अनिवार्य हो जाता है जिससे काले धन की समस्या से मुक्ति मिलती है। कैशलेस व्यवस्था से कर संग्रह भी आसान हो जाता है और यह आर्थिक विकास की गति को तेज करता है, क्योंकि इससे सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य,

नोटबंदी के बाद से देश में डिजिटल लेनदेन के चलन में काफी इजाफा हुआ है।

रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास एवं लोगों के समग्र कल्याण पर खर्च करना आसान हो जाता है। कर संग्रह में वृद्धि होने की वजह से कर वसूली के ढांचे में करों की दरें कम हो जाती हैं। बैंकों में भारी मात्रा में नकदी जमा रहने से ब्याज दरों को कम करने में मदद मिलती है और साथ ही बैंक इस नकदी का इस्तेमाल उत्पादक कार्यों में करने में समर्थ हो जाते हैं। नोटबंदी के बाद से लोगों ने आखिरकार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अन्य उपायों के रूप में प्लास्टिक मुद्रा में विश्वास करना शुरू कर दिया है।

अनु मिश्रा
बिठुना, सिवान

रोजगारपरक शिक्षा से बेरोजगारी का हल

शिक्षित युवाओं के मन में नौकरी-रोजगार के संबंध में सवाल उठते रहते हैं। पढ़ाई के बाद युवाओं के पास केवल डिग्री ही होती है जो उन्हें कई साल की कड़ी मेहनत के बाद मिलती है। इस डिग्री को पाने के लिए उन्हें लाखों रुपये तक खर्च करने पड़ जाते हैं और जब नौकरी का समय आता है तो पता चलता है कि उनके लिए कोई अच्छी नौकरी या रोजगार ही नहीं है। गाहे-बगाहे सामने आने वाली रिपोर्ट और आंकड़े आशंकित करते हैं कि देश में रोजगार की स्थिति काफी गंभीर है। पहले हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, फिर नौकरी पाने के लिए। वर्तमान में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई पूरी करने वाले डिग्रीधारी युवाओं की संख्या करोड़ों में है। डिग्री लेने के बाद भी युवा रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटकता है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता है। सरकारी नौकरियों की संख्या तो बहुत कम है ही, साथ ही निजी क्षेत्र में भी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल रहता है। यदि शिक्षा को रोजगारपरक बना दिया जाए, तो बेरोजगारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है।

गौतम एस.आर.
खंडवा, मध्य प्रदेश

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

चांदी 11 साल में सबसे नरम

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 16 मार्च

धातुओं और ब्रेंट क्रूड के दाम

जिंस	16 मार्च के दाम (रुपये)	अंतर (प्रतिशत)	गिरावट का पिछला दिन
एलएमई तांबा	5,241.0	-4.0	8 नवंबर, 2016
एलएमई जस्ता	1,953.5	-1.6	12 मार्च, 2020
एलएमई निकल	11,855.0	-3.8	12 मार्च, 2020
एलएमई एल्युमीनियम	1,657.0	-1.4	12 मार्च, 2020
एलएमई सीसा	1,706.5	-2.2	27 जून, 2016
सोना (डॉलर/औंस)	1,471.8	-3.7	12 दिसंबर, 2019
सोना (रुपये/10 ग्राम)	39,835.0	-4.8	17 जनवरी, 2020
चांदी (डॉलर/औंस)	12.6	-13.9	1 मई, 2009
चांदी (रुपये/किलोग्राम)	36,640.0	-15.0	11 जून, 2019
ब्रेंट क्रूड (डॉलर/बीबीएल)	30.0	-10.8	26 जनवरी, 2016

एलएमई के दाम (डॉलर प्रति टन) तीन महीने फॉरवर्ड के लिए
स्रोत : ब्लूमबर्ग, संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) पर सोने, चांदी और कच्चे तेल के दाम आज लोअर सर्किट को छू गए। कोरोनावायरस के तेजी से फैलाव के कारण दुनियाभर के इक्विटी बाजारों में बिकवाली हुई है जिससे मार्जिन की भरपाई के लिए सराफा, धातु और ऊर्जा समेत अन्य परिसंपत्ति वर्गों पर दबाव बढ़ा है। वैश्विक बाजारों के घटनाक्रम का घरेलू बाजारों पर भी असर दिखा।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी के दाम मई 2009 के बाद सबसे नीचे आ गए हैं। वहीं कच्चे तेल और धातुओं की कीमतें 2016 से अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। चांदी में अब तक की सबसे अधिक दैनिक गिरावट आई है। यह धातु आज 13 फीसदी लुढ़क गई। मूल धातुओं और वैश्विक कृषि जिंसों की कीमतें भी तेजी से लुढ़कीं क्योंकि विक्रेताओं ने इन जिंसों की कीमतों में और गिरावट से पहले अपने स्टॉक की बिक्री की। सोने में शुरुआत में बढ़त थी, लेकिन बाद में कारोबार में इसमें गिरावट आई।

कॉमट्रेंड्ज के निदेशक ज्ञानशेखर त्यागराजन ने कहा, 'फंडों और निवेश कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों के दौरान सुरक्षित परिसंपत्ति के रूप में चांदी की बड़ी मात्रा में खरीदारी की है। अब वे इसे बेचकर नकदी में बदलना चाहते हैं, जिससे दुनियाभर में चांदी की कीमतें लुढ़की हैं। यह रुझान भारत में भी दिखा है।' वैश्विक बाजार में चांदी के दाम गिरकर 12 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गए हैं। यह इस धातु का मई 2009 के बाद सबसे निचला स्तर है। मुंबई के हाजिर बाजार में कारोबारी कम कीमतों पर बिकवाली के अनिच्छुक नजर आए। मौजूदा नियमों के मुताबिक कुछ जिंसों के लोअर सर्किट को छूने के बाद उनमें कारोबार रोक दिया गया। इन जिंसों में कूलिंग अवधि खत्म होने के बाद फिर से कारोबार शुरू हुआ।

बेंचमार्क एमसीएक्स पर मई 2020 में डिलिवर होने वाली चांदी के दाम 16 फीसदी लुढ़ककर 34,139 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए। इसी तरह अप्रैल में डिलिवरी होने वाला सोने का अनुबंध 4.18 फीसदी गिरकर 38,683 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। कच्चा तेल 9 फीसदी गिरकर 2,179 रुपये प्रति बैरल और तांबा 3.85 फीसदी लुढ़ककर 405 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।

कृषि जिंसों में अरंडी का मार्च डिलिवरी अनुबंध नैशनल कमोडिटी ऐंड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) पर 3.91 फीसदी लुढ़ककर 3,680 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड के सहायक निदेशक किशोर नार्ने ने कहा, 'इक्विटी बाजारों में मार्जिन नुकसान की भरपाई के लिए सराफा, ऊर्जा, धातु और कृषि जैसी जिंसों की बिकवाली हो रही है। कोरोनावायरस के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए उद्यमों को बंद किया जा रहा है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने की चिंताओं के कारण वैश्विक इक्विटी बाजारों में भारी बिकवाली हुई है।'

अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अपनी अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के असर को कम करने के लिए ब्याज दरों को घटाकर लगभग 'शून्य' करने का फैसला किया है। इससे सोमवार को शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी समेत वैश्विक जिंसों के दाम बढ़कर खुले। अमेरिका में ब्याज दरों में लगभग एक फीसदी कटौती से प्रभावी दर घटकर अब 0-0.25 फीसदी पर आ गई है। विश्लेषकों का अनुमान है कि ब्याज दर में कटौती से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 700 अरब डॉलर का राजस्व सृजित होगा। त्यागराजन ने कहा, 'हालांकि कारोबार के कुछ घंटों के भीतर ही सभी परिसंपत्ति वर्गों में व्यापक बिकवाली से यह बढ़त गायब हो गई।' बेंचमार्क लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) पर भारी बिकवाली दबाव के कारण प्रमुख धातुओं की कीमतों में 4-5 फीसदी गिरावट आई। फंडामेंटल अनुकूल नहीं होने के कारण तांबे और जस्ते में गिरावट दर्ज की गई। इन धातुओं को जिंस परिसंपत्ति वर्ग में लघु निवेश विकल्प माना जाता है।

रूस की अति आपूर्ति से मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब ने अपना उत्पादन बढ़ाया है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और गहरी हुई है। दोनों प्रमुख तेल उत्पादक देशों के बीच कीमत की जंग चल रही है।

'एक जिंस, एक एक्सचेंज' का प्रस्ताव

राजेश भयानी
मुंबई, 16 मार्च

भारत को दाम स्वीकार करने वाले देश की अपेक्षा दाम निर्धारित करने वाला देश बनाने के इरादे से भारत में जिंस बाजार के विकास और विस्तार के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 'एक जिंस, एक एक्सचेंज' का प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि वर्तमान में कई एक्सचेंजों ने प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने और निवेशकों को विकल्प देने के लिए एक जैसी जिंस के लिए अनुबंध की अनुमति प्रदान की हुई है।

अब तक एमसीएक्स धातुओं, कीमती धातुओं और ऊर्जा अनुबंधों में प्रमुख भागीदार है, जबकि कृषि खंड में एनसीडीईएक्स तथा हीरा, धान और इस्पात में आईसीईएक्स प्रमुख भागीदार हैं। हालांकि विनियामक के अनुसार बीएसई और एनएसई कारोबार बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं और सेबी का तर्क है कि अगर एक्सचेंज किसी एक या दो खास जिंसों पर ही ध्यान केंद्रित करें तो वे उन जिंसों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और उन्हें ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। सेबी द्वारा इस नए प्रस्ताव की दिशा में बढ़ने का कारण यह है कि मौजूदा प्रणाली में एक्सचेंजों का ध्यान अपने स्वयं के जिंसों में बाजार विकसित करने और तरलता को एक से ज्यादा एक्सचेंजों में बांटने के बजाय प्रतिस्पर्धा की ओर है।

उद्योग के एक अधिकारी ने कहा कि जिंसों के अनुबंध के लिए उत्पाद के पेटेंट के समान दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जब कोई एक्सचेंज भलीभांति तरीके से शोध करता है और किसी अनुबंध की शुरुआत करता है तो दूसरों के लिए उसकी नकल करना आसान होता है। इस तरह सेबी का प्रस्ताव अच्छा है क्योंकि जब कोई एक्सचेंज कुछ विशिष्टता लाता है, तो उसे उक्त अनुबंध में तरलता निर्मित और विकसित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन और समय की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि सेबी भारतीय जिंस बाजार के लिए चीन जैसा मॉडल अपनाता दिखाई दे रहा है।

अब तक भारत गेहूं, चावल, दलहन, मसालों, कपास, चाय, रबर, लौह अयस्क, इस्पात, सोने, चांदी और हीरे का एक प्रमुख उपभोक्ता है। हीरे, चावल, रबर, चीनी, लौह अयस्क आदि के मामले में भारत प्रमुख आयातक या निर्यातक के रूप में वैश्विक बाजार में बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन अब भी भारत वैश्विक दाम निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है। सेबी ने हाल ही में इस विषय पर जारी एक अवधारणा पत्र का अवलोकन करते हुए पाया है कि कुछ एक्सचेंज जब केवल एक या दो जिंसों में ही आगे बढ़ते हैं तो वे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उदाहरण के लिए चीन कई जिंसों का एक प्रमुख उत्पादक या उपभोक्ता रहा है, लेकिन इसके द्वारा कुछ विशेष जिंसों पर केंद्रित एक्सचेंजों की शुरुआत किए जाने के बाद वह उन जिंसों और दामों के संबंध में वैश्विक कीमतों को प्रभावित करने लगा है और वह उन जिंसों को भी प्रभावित कर रहा है जिनका रुख पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है।

सेबी के अवधारणा पत्र के अनुसार डालियान कमोडिटी एक्सचेंज की प्रमुख जिंस सोयाबीन, लौह अयस्क और अंडा हैं। झेंगझऊ जिंस एक्सचेंज की प्रमुख जिंस पीटीए, सेब और कपास हैं। शांघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज की प्रमुख जिंस रबर है। शांघाई गोल्ड एक्सचेंज और शांघाई इंटरनैशनल गोल्ड एक्सचेंज केवल सोने, चांदी और प्लैटिनम में ही कारोबार करते हैं।

दुनिया के अन्य स्थानों में भी यह विचार सफल रहा है तथा लंदन मेटल एक्सचेंज गैर-लौह धातुओं में और टोक्यो कमोडिटी एक्सचेंज रबर में अग्रणी रहा है। सेबी भारत में भी इसी तरह का मॉडल विकसित करना चाहता है जहां एक्सचेंजों को एक जिंस का चयन करना होगा जिसमें केवल वही एक्सचेंज कारोबार कर सकेगा और उन्हें तीन से पांच साल में उस जिंस के लिए बाजार विकसित करना होगा। इस अवधि के बाद अन्य एक्सचेंजों को इसमें कारोबार करने अनुमति दी जा सकती है।

एनएमडीसी ने घटाई लौह अयस्क की कीमत

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 16 मार्च

एनएमडीसी ने लौह अयस्क की कीमतों में 50 रुपये या करीब 1.5 फीसदी की कमी की है जो 14 मार्च, 2020 से प्रभावी होगा। इस तारीख से अयस्क टुकड़े का भाव 3,150 रुपये प्रति टन और अयस्क चूरे का भाव उससे 2 फीसदी कम 2,860 रुपये प्रति टन तय किया गया है। कीमतों में रॉयल्टी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड (डीएमएफ), नैशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एनएमईटी), उपकर, वन परमिट शुल्क और दूसरे करों को शामिल नहीं किया गया है।

इससे पहले अयस्क टुकड़े की कीमत 3,200 रुपये प्रति टन और चूरे की कीमत 2,910 रुपये प्रति टन थी जो 19 जनवरी, 2020 से प्रभावी था। ये कीमतें एक वर्ष पहले के मुकाबले अधिक हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 3 अप्रैल, 2019 को अयस्क टुकड़े की की कीमत 2,850 रुपये प्रति टन थी और चूरे की कीमत 2,610 रुपये प्रति टन थी जो 3 अप्रैल, 2019 से प्रभावी था।

कीमत में कटौती ऐसे समय पर की गई है जब लौह अयस्क के बड़े उपभोक्ता इस्पात, घरेलू इस्पात कीमतों और मांग में कमी आ रही है।

स्टील का इस्तेमाल करने वाले उपयोकर्ताओं की ओर से कम मांग के कारण 2019 के ज्यादातर समय घरेलू इस्पात कीमतों में तेजी से और लगातार कमी आई थी। इसकी वजह वाहन उद्योग में घटी मांग और अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती को बताया गया था। वित्त वर्ष 2020 में अप्रैल से फरवरी के दौरान घरेलू इस्पात की खपत महज 3.8 फीसदी बढ़ी जबकि गत वर्ष की समान अवधि में यह 8.8 फीसदी बढ़ी थी।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Mar 16	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,677.0	-4.9	1,885.0	-0.8
Copper	5,530.5	-10.2	5,937.8	-7.5
Nickel	12,565.0	-10.8	12,521.9	-14.5
Lead	1,781.0	-4.9	1,938.9	-12.3
Tin	16,400.0	-4.5	16,493.9	-8.1
Zinc	1,986.5	-12.5	2,100.4	-18.9
Gold ($/ounce)	1,460.3*	-1.1	1,668.2	0.5
Silver ($/ounce)	12.3*	-27.9	15.3	-20.7
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	28.9*	-56.9	33.5	-49.1
Natural Gas ($/mmBtu)	1.8*	-23.1	1.8	-21.8
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	180.8	-5.3	269.3	-10.5
Maize	181.0*	-2.5	219.3	-23.3
Sugar	343.4*	-2.4	464.8	-4.3
Palm oil	577.5	-19.8	942.5	-16.3
Rubber	1,466.1*	-8.4	1,750.4	-6.2
Coffee Robusta	1,215.0*	-14.8	1,811.0	-4.4
Cotton	1,284.9	-13.0	1,416.1	-11.2

* As on Mar 16, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 74.3 & 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	71.7	41183
Oil and Oilseeds	287.7	82468
Spices	0.5	8
Metal(Mar 13)		
Metal- non ferrous	8559.4	35827
Metal- precious	24578.5	425
Oil and gas(Mar 13)		
Gas	2919.7	21995
Oil	8938.6	1734

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	144.7	113414
Grains	119.8	79805
Oil and Oilseeds	524.4	342505
Others	66.2	58060
Pulses	116.2	45340
Spices	52.3	18571

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Nickel (Mar 31)	922.5	3.1
Crude Oil (Mar 19)	2396.0	2.9
Natural Gas (Mar 26)	139.8	0.7
Zinc (May 29)	155.9	0.4
Aluminium Mini (Mar 31)	137.3	0.2
Losers (* % Change)		
Silver (May 05)	40487.0	-8.3
Silver Mini (Apr 30)	40553.0	-8.2
Silver Micro (Apr 30)	40766.0	-7.7
Gold (Apr 03)	40348.0	-4.4
Gold Mini (Apr 03)	40382.0	-4.3
Gold Petal (Mar 31)	4022.0	-3.6
Cardamom (Apr 15)	2314.2	-3.6

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Chana-Bikaner (Mar 20)	3929.0	0.9
Barley Jaipur (Apr 20)	1630.0	0.3
Jeera Unjha (Mar 20)	13435.0	0.3
Losers (* % Change)		
Soyabean Indore (Mar 20)	3332.0	-4.0
Guar Seed 10 (Mar 20)	3404.0	-3.8
GuarGum 5T-Jodhpur (Mar 20)	5365.0	-3.6
CottonSeed Oil-Akola (Mar 20)	1750.0	-3.6
CastorSeed New-Disa (Mar 20)	3746.0	-2.4
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	982.0	-1.9
Coriander-Kota (Apr 20)	5540.0	-1.9
Mustard Seed Rape Oil (Apr 20)	3836.0	-1.7
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	5348.0	-1.3

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Silver Micro-Ahemd (Apr 30)	40766.0	14.1
Silver Ahm (May 05)	40487.0	13.3
Gold Ahm (Apr 03)	40348.0	1.2
Nickel Mumbai (Mar 31)	922.5	1.2
Copper Mum (Mar 31)	421.8	1.0
Gold Petal-Mumbai (Mar 31)	4022.0	0.5
Discount over spot price (In %)		
Cardamom Vandanmedu (Apr 15)	2314.2	-13.2
Menthol Oil Chandaus (Mar 31)	1127.7	-12.5
Lead Min Mumbai (Mar 31)	141.1	-4.0
Zinc Mini Mumbai (Mar 31)	151.8	-3.4
Cotton-Rajkot (Mar 31)	17880.0	-2.6
Alumini-Mumbai (Mar 31)	137.3	-2.4

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Maize-Sangli (Mar 20)	1629.0	8.2
Crude Palm Oil Kandl (Mar 31)	637.0	3.0
Bajra-Jaipur (Mar 20)	1649.0	0.5
Paddy-Basmati-Karnal (Mar 20)	2979.0	0.1
29 mm Cotton-Rajkot (Mar 20)	18410.0	0.0
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1630.0	-9.3
Soy Bean Indore (Mar 20)	3332.0	-7.7
Coriander-Kota (Apr 20)	5540.0	-6.3
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	5348.0	-4.8
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Mar 20)	5365.0	-2.5
Jeera Unjha (Mar 20)	13435.0	-0.7

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	107.....(107)
Aluminium ingots /kg	140.....(140)
Brass sheet cutting /kg	310.....(315)
Brass utensil scraps/kg	298.....(298)
Copper heavy scrap /kg	409.....(410)
Copper utensil scraps/kg	378.....(381)
Copper wire bar /kg	441.....(443)
Lead ingots /kg	144.....(148)
Nickel Cathodes /kg	930.....(955)
Tin slabs /kg	1225.....(1255)
Zinc slabs /kg	156.....(158)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10292.....(10095)
DCH - 32 /Qtl	11023.....(10995)
Jaydhar /Qtl	9392.....(9392)
Shankar- 6 /Qtl	10826.....(10798)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai
Castor FSG /10kg	830.....(835)
Castor Comm /10kg	820.....(825)
Ricebran oil/10kg	-.....(820)
Groundnut oil /10kg	1250.....(1230)
Linseed oil /10kg	-.....(895)
Karanji /10kg	-.....(790)
Palm oil /10kg	718.....(725)
Sunflower exp ref /10kg	810.....(815)
Sunflower oil exp /10kg	730.....(735)
Soyabean ref / 10kg	765.....(765)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3332-3572 .....(3300-3572)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	30.09.....(31.73)
Brent Crude (UK)	30.85.....(33.55)
Brent Crude (WTI)	31.73.....(31.73)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	1.83.....(1.87)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	184.42.....(196.07)
Naptha spot /Rs/MT	-.....(45170)
LSHS spot/ M.T.	-.....(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	-.....(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	39835.....(41849)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	39995.....(42017)
Silver.999/ kg	36640.....(43085)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18388.45	18402.10
Alumini-Mumbai (M)	1 K	142.40	140.70
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1625.00	1650.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1646.65	1640.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	1841.25	1797.00
Basmati-Amritsar (I)	100 KG	3284.00	3232.00
Cardamom-Vand. (I)	1 K	2650.00	2700.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	3963.75	3881.25
Castor Seed-Kadi (N)	X	3850.00	3850.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	3868.75	3922.20
Chana Delhi (N)	1 Q	4025.75	4114.70
Chana-Akola (N)	X	3800.00	3831.25
Coriander-Gondal (N)	X	5850.00	5704.00
Coriander-Jaipur (N)	X	5851.25	5600.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	5922.45	5912.20
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1826.35	1826.50
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1874.75	1882.75
Cotton-Kadi (N)	1 B	18420.45	18381.60
CPO-Kandla (M)	10 K	634.90	615.50
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	635.25	618.40
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	630.00	620.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	917.10	919.45
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1588.80	1592.85
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3585.55	3590.25
Gold Ahm (M)	10 G	41859.00	39867.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	33622.00	32022.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4194.00	4003.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	5612.50	5500.00
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3466.90	3425.00
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3400.00	3370.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1075.90	1075.25
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	104.05	104.00
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	14400.00	14300.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	13511.10	13525.00
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	785.65	785.00
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	980.80	986.15
Kapas-Rajkot (N)	X	980.65	979.20
Lead Mum (M)	1 K	148.70	147.00
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1685.00	1600.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	1806.65	1769.45
Maize-Erode (N)	X	1442.50	1466.65
Maize-Feed/Ind- Gula (N)	1 Q	1806.65	1769.45
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	1700.00	1700.00
Maize-Sangli (N)	X	1487.30	1505.00
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4300.00	4350.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7610.00	7640.00
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4076.50	3973.50
Nickel Mumbai (M)	1 K	958.20	911.70
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	2975.00	2975.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3018.00	2994.00
Paddy-Basmati-Pusa (N)	X	2725.00	2731.25
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	319.00	319.40
Pepper-Kochi (N)	1 Q	31975.00	32083.35
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	793.75	796.25
Rape mustards-Patan (I)	20 K	710.00	725.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1909.45	1920.00
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5400.00	5337.00
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	710.00	700.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	769.95	768.80
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	775.10	771.50
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	785.00	785.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13100.00	13000.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13088.00	13083.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	42984.00	35726.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	3616.00	3609.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	3434.00	3434.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	3711.75	3610.75
Soy Bean-Akola (N)	X	3500.00	3475.00
Soymeal Indore (N)	1 T	29438.00	29375.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	768.80	769.00
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	29200.00	29200.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	30000.00	30000.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	27400.00	27400.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3170.00	3150.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3290.50	3266.65
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3201.65	3206.65
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3361.90	3366.65
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3207.45	3203.20
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3101.65	3108.35
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5650.00	5616.65
Wheat Delhi (N)	1 Q	2200.00	2200.00
Wheat Kota (N)	1 Q	1997.80	2005.00
Wheat New Indore (N)	1 Q	1850.00	1800.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2070.00	2013.75
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	1772.50	1741.65
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5650.00	5600.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	4250.00	4400.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	157.80	157.15

* as on Mar 13, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION
दिवस सत्र (सोमवार)
कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Mar 31	18060, 18100, 17830, 17880	3954	591	26097
Apr 30	18300, 18350, 18060, 18120	2402	363	13163
May 29	18510, 18600, 18400, 18410	225	39	1033
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Mar 20	1780, 1790, 1744, 1750	10520	314	15330
Apr 20	1805, 1811, 1758, 1759	52030	2916	71760
May 20	1809, 1823, 1769, 1770	7180	575	19870
Jun 19	1820, 1855, 1820, 1833	660	50	3520
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	984, 990, 980, 981.5	296	49	720
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	990, 993, 980, 982	974	513	2804
Grains				
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	3506, 3506, 3398, 3404	4985	223	12295
Apr 20	3470, 3470, 3370, 3370	27380	2734	55585
May 20	3438, 3480, 3392, 3404	2735	420	5445
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	3840, 3840, 3690, 3746	1360	109	920
Apr 20	3770, 3770, 3670, 3680	6530	800	18915
May 20	3742, 3750, 3664, 3676	1760	233	7815
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Mar 31	617, 624, 606, 607.8	23430	1847	30030
Apr 30	603, 615, 595.6, 597	16150	1179	40330
May 29	605, 612.1, 592.9, 595.6	4010	284	11810
Mentha Oil MCX(1 K)				
Mar 31	1165.7, 1173.4, 1121, 1127.7	126	305	165.6
Apr 30	1129, 1129.9, 1080, 1096.1	64.44	126	103.68
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Apr 20	3913, 3929, 3822, 3836	12690	1091	16770
May 20	3884, 3933, 3825, 3833	6780	506	11220
Jun 19	3940, 3960, 3840, 3843	1280	88	1690
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Mar 20	743.8, 754, 740, 745.2	1920	199	17800
Apr 20	710.2, 723, 702.2, 705	19505	2488	37650
May 20	699.4, 711, 688.8, 693.2	3565	462	6605
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Mar 20	3420, 3490, 3332, 3332	15435	1109	3115
Apr 20	3402, 3430, 3298, 3308	37090	3692	131180
May 20	3378, 3404, 3280, 3282	10785	1281	67265
Jun 19	3368, 3410, 3282, 3284	4960	543	21335
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	5400, 5423, 5345, 5365	830	59	920
Apr 20	5540, 5560, 5439, 5439	8780	894	51425
May 20	5563, 5563, 5472, 5483	2525	184	5690
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	3844, 3961, 3836, 3929	4110	106	1950
Apr 20	3779, 3830, 3732, 3794	17760	1254	26480
May 20	3800, 3868, 3768, 3821	5560	429	12500
Jun 19	3853, 3899, 3840, 3853	2980	196	4390
Spices				
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 20	5481, 5580, 5431, 5540	2500	236	6070
May 20	5526, 5610, 5490, 5566	1190	109	2730
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Mar 20	13225, 13490, 13225, 13435	159	30	186
Apr 20	13050, 13145, 12950, 13125	981	281	2382
May 20	13040, 13185, 12980, 13105	96	32	318
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	5398, 5400, 5314, 5348	210	38	200
Apr 20	5518, 5518, 5354, 5426	1930	294	5850
May 20	5480, 5486, 5366, 5448	760	53	765
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Mar 31	136.8, 137, 136.05, 136.3	4397	3236	3864
Apr 30	137, 137.1, 136.5, 137	730	531	1517
Copper MCX(1 K)				
Mar 31	419.15, 419.15, 407.5, 408.35	22757.5	7576	8912.5
Apr 30	422, 422, 411.2, 412.45	1295	479	1217.5
Lead Mini MCX(1 K)				
Mar 31	140.55, 140.85, 139.05, 139.2	9257	6518	5108
Apr 30	140.5, 140.85, 139.15, 139.3	319	300	1213
Nickel MCX(1 K)				
Mar 31	917.8, 917.8, 886.7, 889.6	15007.5	9194	1983
Apr 30	909.2, 910.1, 885.3, 887.2	273	176	664.5
Zinc Mini MCX(1 K)				
Mar 31	151.85, 151.85, 149.6, 149.8	24254	15180	14840
Apr 30	153, 153.25, 151.8, 152.05	1374	968	4093
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Apr 03	40982, 41199, 38919, 39177	17.68	15053	8.07
Jun 05	41498, 41554, 39290, 39543	3.06	2530	13.5
Aug 05	41685, 41685, 40037, 40866	0.09	80	0.26
Gold Guinea MCX(8 G)				
Mar 31	33370, 33600, 31803, 31946	0.02	2013	0.01
Apr 30	33333, 33545, 31703, 31925	0.01	597	0.01
Gold Mini MCX(10 G)				
Apr 03	40802, 41291, 39019, 39222	4.96	43608	0.7
May 05	41000, 41444, 39236, 39420	0.56	4764	0.42
Jun 05	41350, 41620, 39500, 39576	0.02	220	0.04
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Mar 31	4033, 4082, 3802, 3864	0.02	5288	0.01
Apr 30	4144, 4145, 3882, 3911	0.01	2447	0.01
Silver MCX(1 K)				
May 05	40962, 41099, 35629, 35777	924.48	24840	308.34
Jul 03	41500, 41537, 36106, 36272	22.65	699	7.38
Silver Micro MCX(1 K)				
Apr 30	41385, 41474, 35900, 36237	129.48	92041	32.95
Jun 30	41800, 42000, 36560, 36932	14.16	11059	4.22
Silver Mini MCX(1 K)				
Apr 30	40546, 41104, 35100, 35738	356.88	57096	67.12
Jun 30	41790, 41790, 35892, 36438	17.79	3107	4.26
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Mar 26	136.6, 138.3, 133, 133.8	75214mb	37917	22644mb
Apr 27	141.4, 142.2, 137.2, 137.9	3418mb	2131	2811mb
May 26	144.9, 147.3, 142, 142.7	243mb	117	425mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Mar 19	2334, 2343, 2201, 2216	13987bl	84114	1750bl
Apr 20	2433, 2433, 2262, 2275	1038bl	7462	687bl
May 18	2497, 2497, 2336, 2373	14bl	81	21bl

सायं सत्र (शुक्रवार)
कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Mar 31	17820, 18450, 17760, 18210	8389	1366	26522
Apr 30	18120, 18650, 18020, 18470	4702	653	12823
May 29	18380, 18870, 18380, 18730	1254	198	927
Jun 30	19210, 19210, 19010, 19150	183	9	170
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	977.5, 1005, 964, 994.5	1068	194	704
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	985, 1005.5, 962, 995	2375	1537	2665
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Mar 31	599, 630.9, 589.1, 619.7	61760	4081	29670
Apr 30	592.2, 623.3, 580.4, 610.2	41690	2598	37430
May 29	578.7, 618.4, 575, 606.6	6710	467	10010
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Mar 20	731.2, 758, 728.2, 743.2	7185	800	18535
Apr 20	705, 731, 687.2, 716.4	47270	5266	37255
May 20	698.2, 720.2, 678.4, 706.6	7475	1013	5260
Jun 19	698.4, 707.6, 698.4, 701.2	70	7	80
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Mar 31	136.45, 138.7, 136, 137.3	14107	10336	3160
Apr 30	137.2, 138.6, 136.7, 137.55	989	800	1080
Copper MCX(1 K)				
Mar 31	415.65, 427.7, 413.65, 421.8	53385	17554	7297.5
Apr 30	421, 430.5, 418, 425.35	2362.5	893	1077.5
Lead Mini MCX(1 K)				
Mar 31	141.75, 143.8, 140.5, 141.05	27609	18895	3895
Apr 30	141.9, 143.5, 140.5, 141.15	1304	1119	1175
Nickel MCX(1 K)				
Mar 31	895.1, 950.9, 887.8, 922.5	46783.5	28494	1239
Apr 30	893, 947.3, 887.4, 917.6	1789.5	1090	654
Zinc Mini MCX(1 K)				
Mar 31	151.9, 155.5, 149.3, 151.8	66512	43610	12317
Apr 30	152.8, 157.5, 151.4, 153.95	6089	4354	3836
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Apr 03	41750, 42070, 40055, 40348	25.32	21114	8.24
Jun 05	42193, 42680, 40511, 40790	5.6	4472	13.25
Aug 05	42802, 42802, 41000, 41021	0.13	108	0.2
Gold Guinea MCX(8 G)				
Mar 31	34010, 34249, 32622, 33053	0.03	2776	0.01
Apr 30	33565, 34398, 32750, 32969	0.01	915	0.01
Gold Mini MCX(10 G)				
Apr 03	42000, 42085, 40155, 40382	6.66	56709	0.77
May 05	41946, 42400, 40400, 40638	0.88	6569	0.45
Jun 05	42083, 42607, 40580, 40831	0.06	390	0.04
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Apr 30	4197, 4198, 4023, 4061	0.01	2866	0
Mar 31	4157, 4161, 4001, 4022	0.03	7415	0.01
Silver MCX(1 K)				
May 05	43280, 43542, 40400, 40487	1295.52	35221	299.34
Jul 03	43380, 44017, 40912, 41029	25.62	745	4.8
Silver Micro MCX(1 K)				
Apr 30	44020, 44020, 40650, 40766	197.6	145405	34.94
Jun 30	44730, 44730, 41295, 41404	17.64	14139	3.93
Silver Mini MCX(1 K)				
Apr 30	43230, 43577, 40444, 40553	477.2	78441	56
Jun 30	43498, 44203, 41110, 41207	13.4	2523	3.38
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Mar 26	138.6, 144.9, 135, 139.8	196499mb	103275	18924mb
Apr 27	140.8, 148.2, 140.5, 143.5	9415mb	6262	2645mb
May 26	146.7, 153.2, 146.5, 148.5	555mb	370	426mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Mar 19	2342, 2511, 2316, 2396	35161bl	226556	1215bl
Apr 20	2376, 2571, 2376, 2458	1819bl	14194	510bl
May 18	2490, 2625, 2420, 2528	12bl	101	8bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

नई दिल्ली | 17 मार्च 2020 मंगलवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

कंपनियां कर्मचारियों खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को घर से काम की दे रहीं छूट

घर से काम करने पर जोर

कोका-कोला, गोदरेज कंज्यूमर और उबर जैसी कंपनियों ने कर्मचारियों को घर से काम करने का विकल्प दिया है, लेकिन उन्हें लैपटॉप और फोन के जरिये जुड़े रहना होगा

बीएस संवाददाता

कोरोनावायरस की मार अब बड़े औद्योगिक समूहों पर भी पड़ने लगी है। प्रौद्योगिकी और नए जमाने की कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को इस संकट से बचाने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं। अब टाटा और रिलायंस जैसे बड़े परंपरागत औद्योगिक समूह भी इस महामारी से अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए असामान्य उपाय कर रहे हैं। इस मामले में भारतीय कंपनियों की एक राय है। वे अपने कर्मचारियों को अनावश्यक यात्रा से बचने, बैठकों की संख्या सीमित करने और साफ-सफाई के कड़े उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। कुछ कंपनियां कर्मचारियों को घर से काम करने और खुद को भीड़ से अलग रखने की सलाह दे रही हैं।

विनिर्माण संयंत्रों में अभी तक यह चलन शुरू नहीं हुआ है। सेवा क्षेत्र के उलट विनिर्माण क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने परिसरों के बाहर निकलकर ज्यादा यात्रा करने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह वे स्वाभाविक रूप से सुरक्षित माहौल में रहते हैं। विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े कारोबारी समूह कोरोनावायरस से खतरे से निपटने के लिए दूसरे कई उपाय भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए रिलायंस के परिसरों में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के शरीर के तापमान की जांच की जा रही है। रिलायंस के प्रवक्ता ने कहा, 'हमने हर किसी को कहा है कि अगर किसी को फ्लू जैसे लक्षण हैं, उसे खुद को अलग-थलग रखना चाहिए। सौभाग्य से पिछले एक महीने से हमारे कर्मचारियों ने ज्यादा अंतरराष्ट्रीय यात्रा नहीं की है और हमें अपने किसी भी कार्यकारी को अलग-थलग करने की जरूरत नहीं पड़ी।'

रिलायंस ने स्थिति पर नजर रखने के लिए एक विशेष टीम बनाई है जो रोजाना चेयरमैन और कार्यकारी निदेशकों को जानकारी देती है। ऐसी बैठकों से परहेज किया जा रहा है जिनमें एक ही कमरे में 20 से अधिक लोगों के जुटने की जरूरत है। देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी मारुति सूजुकी ने अपने कर्मचारियों को बैठकों में हिस्सा लेने के बजाय टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करने को कहा है। टाटा संस में कम से कम दो कर्मचारियों को अलग रखा गया है और वे घर से काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी हाल में कोरोनावायरस से प्रभावित देशों से लौटे हैं।

एक जानकार ने कहा, 'इन लोगों के नमूने पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं, एहतियात के तौर पर उन्हें अलग रखा गया है।' होल्डिंग कंपनी ने टाटा समूह के कर्मचारियों को परामर्श जारी कर गैर-जरूरी यात्राओं और भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी है।

एहतियात जरूरी

- कर्मचारियों को विदेश यात्रा न करने, घरेलू यात्रा में कमी लाने का सुझाव दिया गया है
- जिनमें कोविड-19 के लक्षण दिख रहे हैं या वे प्रभावित देशों की यात्रा पर गए थे तो उन्हें अलग रहने को कहा जा रहा है
- समूह बैठक न करने और हाथों की साफ-सफाई पर ध्यान देने को कहा गया है
- कंपनियां कर्मचारियों खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को घर से काम करने की छूट
- बायोमेट्रिक उपस्थिति बंद करने का आदेश भी दिया जा रहा है

टाटा स्टील ने घरेलू और विदेशी सभी कारोबारी यात्राएं अगले नोटिस तक स्थगित कर दी हैं। कंपनी ने फिलहाल एहतियात के तौर पर बायोमीट्रिक आधारित हाजिरी प्रणाली को बंद कर दिया है। कोल इंडिया ने अपने कर्मचारियों को हाथ मिलाने से परहेज करने और नमस्ते का इस्तेमाल करने को कहा है।

आईटीसी भी संभावित खतरे की स्थिति में कारोबार जारी रखने के लिए योजना बना रही है। कंपनी ने अपने परिसरों में सैवलॉन हैंड डिस्पेंसर को मुख्य स्थानों पर रखा है। इस कंपनी ने भी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर पाबंदी लगा रखी है। विदेश से आने वाले कर्मचारी को सबसे पहले कंपनी के डॉक्टर से मिलने को कहा जा रहा है।

कोका-कोला, गोदरेज कंज्यूमर और उबर जैसी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने का विकल्प दिया है लेकिन उन्हें लैपटॉप और फोन से जुड़े रहने को कहा गया है। इसके कारण मुंबई के प्रमुख कारोबारी केंद्रों बांद्रा, बीकेसी और वर्ली में चहल-पहल बहुत कम हो गई है।

जिन कंपनियों ने अभी तक अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति नहीं दी है, जल्दी ही वे भी इस राह पर चलने वाली हैं। सोमवार से स्टार इंडिया के कर्मचारी घर से काम करेंगे। स्टार इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा, 'कोविड-19 के खतरे को कम से कम करने के लिए हमने पूरे देश में अपने कर्मचारियों को अगले आदेश तक घर से काम करने को कहा है।'

लेकिन उन कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश देना मुश्किल हो रहा है जो स्टॉक मार्केट व्यवस्था से जुड़ी हैं। म्युचुअल फंड मैनेजरों को भेदिया कारोबार या फ्रंट रनिंग के खतरे को कम करने के लिए कुछ व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ता है। विश्लेषकों के साथ-साथ उन्हें दफ्तर की सुविधाओं का व्यापक इस्तेमाल करना पड़ता है। इनमें डेटा टर्मिनल भी शामिल हैं जिन्हें घर से दोहराना मुश्किल है।

उद्योग के एक अधिकारी ने कहा कि अगर स्थिति और बदतर होती है तो उन्हें कुछ काम घर ले जाने के लिए नियामकीय मंजूरी मांगनी पड़ सकती है। इस बीच सक्रिय ग्राहकों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म जीरोधा ने अपने 1,200 कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है। महिन्द्रा समूह जैसी कई कंपनियों ने गर्भवती महिला कर्मचारियों को दफ्तर नहीं आने को कहा है। बीमा कंपनी एचडीएफसी लाइफ ने सभी गर्भवती महिलाओं को घर से काम करने का विकल्प दिया है।

एक अन्य बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी आपात योजना की तैयारी में जुटी है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में अंडरराइटिंग, रिइंश्योरेंस और क्लैम्स के प्रमुख संजय दत्ता ने कहा, अगर हमारे कर्मचारियों को घर से काम करना पड़े तो हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमने इसका अभ्यास किया है। हम अपने उपभोक्ताओं को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं और उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कोरोवायरस के कारण अस्पताल में भर्ती होने का कवर शामिल है।'

देश की कई दवा कंपनियों ने अपनी सेल्स कॉन्फ्रेंस और घरेलू यात्राएं रद्द कर दी हैं। एक प्रमुख कंपनी ने कहा, 'हॉस्पिटल सेल्स टीमें डॉक्टर से नहीं मिल सकते हैं क्योंकि उन्हें अधिकांश परिसरों में जाने की अनुमति नहीं है।' प्रमुख दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल में सामान्य कामकाज चल रहा है लेकिन वहां हैंड सैनिटाइजर, साफ सफाई और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यापक व्यवस्था की गई है। वोडाफोन आइडिया ने यात्रा, साफ-सफाई और घर से काम करने के विकल्प के बारे में अपने कर्मचारियों को परामर्श जारी किया है।

देश की शीर्ष लॉ फर्में भी एहतियाती कदमों की तैयारी कर रही हैं। जे सागर एसोसिएट्स में पार्टनर और कार्यकारी समिति के सदस्य दीना वाडिया ने कहा कि कंपनी ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी योजनाएं बनाकर रखी है। इनमें गैर जरूरी यात्राओं पर प्रतिबंध और घर से काम की सुविधा शामिल है। उन्होंने कहा कि कंपनी इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कर्मचारियों को आधा दिन घर से काम करने को कहा जा रहा है। इस सप्ताह कुछ दिन पूरी तरह घर से काम करने की भी अनुमति दी जा रही है। शार्दुल अमरचंद मंगलदास ऐंड कंपनी में पार्टनर श्वेता श्रॉफ चोपड़ा ने भी कहा कि जिस दिन भारत में कोरोनावायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई, उसी दिन से कंपनी ने सारे एहतियाती उपाय शुरू कर दिए थे। देशभर में सभी कार्यालयों में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रोटोकॉल को लागू किया गया है, सुरक्षा संसाधनों (60 फीसदी एल्कोहल आधारित सैनिटाइजर, मास्क, डिस्पोजेबल क्रॉकरी) के उपाय किए गए हैं, बायोमीट्रिक एक्सेस को बंद कर दिया गया है और साफ-सफाई के उपाय किए गए हैं।

(पवन लाल, सुब्रत पांडा, समी मोडक, अभिजित लेले, मेघा मनचंदा, शैली सेठ मोहिले, ईशिता आयान दत्त, अभिषेक रक्षित, विवेट सुजन पिंटो, राघवेंद्र कामत, विनय उमरजी, जश कृपलानी और सोहिनी दास)

मिलकर खर्च करें देश: आईएमएफ प्रमुख

- अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने कहा कि 20 देशों ने वित्तीय मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि वायरस से बनी परिस्थितियों का सामना करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों को एक साथ मिल कर खर्च करने की जरूरत है।
- मंदी की आशंका के बीच बैंक ऑफ जापान ने आपात बैठक बुलाई। वहीं न्यूजीलैंड के केंद्रीय बैंक ने भी नीतिगत ब्याज दर में कटौती की
- इटली में कोरोनावायरस की वजह से एक दिन में 368 लोगों की मौत हो गई। रविवार तक इटली में मरने वालों की कुल तादाद 1,809 हो गई जबकि 24,747 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई
- वायरस प्रकोप के मद्देनजर जर्मनी ने सोमवार से ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, लक्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड के साथ लगी सीमाओं पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है
- फ्रांस में कोरोनावायरस का कहर बेहद चिंताजनक है और स्थिति तेजी से बिगड़ रही है
- अमेरिका में वायरस के चलते 69 लोगों की जान चली गई है और 3,700 से अधिक लोग संक्रमित हैं
- वायरस के बढ़ते कहर के मद्देनजर न्यूयॉर्क में सोमवार से सभी स्कूल, रेस्तरां और बार भी बंद रहेंगे तथा केवल सामान घर ले जाने की सुविधा होगी
- कोरोनावायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो ने राजधानी काराकास सहित सात राज्यों की सीमाएं सील करने का आदेश दिया है
- ऑस्ट्रेलिया में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या सोमवार को बढ़कर 350 हो गई
- देश के कुछ राज्यों ने आपातकाल जैसी स्थिति घोषित करते हुए अलग रहने के नियमों को तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया है
- पाकिस्तान में कोरोनावायरस संक्रमण के 41 नए मामले सामने आने के साथ ही सोमवार को देश में इसका आंकड़ा बढ़कर 94 हो गया है। रविवार तक कोरोनावायरस के संक्रमितों की संख्या 53 थी
- वहीं दक्षिण अफ्रीका ने कोरोनावायरस संकट को लेकर देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 61 पर पहुंच गई है।
- चीन में विदेश से आने वाले लोगों में कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। सोमवार को भी संक्रमण के ऐसे ही 12 नए मामले सामने आए।
- ईरान में कोरोनावायरस से 129 और लोगों की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 853 हुई।
- कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के मद्देनजर तुर्की ने सऊदी अरब से लौट रहे हजारों धार्मिक यात्रियों को अलग रखा है।
- स्पेन में सोमवार को वायरस संक्रमण के करीब 1,000 नए मामले आए और कुल संक्रमितों की तादाद बढ़कर 7,753 हो गई। वहीं, बहरीन में कोरोनावायरस से पहली मौत हुई है
- नीदरलैंड में संक्रमण की वजह से सभी स्कूल, कैफे, रेस्तरां और स्पोर्ट्स क्लब रहेंगे बंद
- दक्षिण कोरिया में संक्रमण के 74 नए मामले की पुष्टि हुई। देश में कुल 8,236 लोग संक्रमित हैं

एजेंसियां

यूरोप से हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध

अनीश फडणीस

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सोमवार को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए यूरोप से आने वाली सभी यात्री उड़ानों को बुधवार 31 मार्च तक निलंबित करने का आदेश दिया है।

उपमहानिदेशक सुनील कुमार ने एक सर्कुलर में कहा, '18 मार्च से यूरोपीय संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, तुर्की तथा ब्रिटेन के सदस्य देशों के यात्रियों का भारत में प्रवेश प्रतिबंधित है। इस आदेश के बाद ग्रीनविच समय 12:00 बजे के बाद से कोई भी विमान इन देशों के किसी भी यात्री को लेकर उड़ान नहीं भरेगा। विमानन कंपनियों किसी भी उड़ान के शुरूआती स्थान से इसे लागू करेंगीं। ये निर्देश अस्थायी उपाय हैं जो 31 मार्च तक लागू रहेंगे और बाद में इनकी समीक्षा की जाएगी।'

31 मार्च तक बंद रहेंगी उड़ानें

यह आदेश भारतीय यूरोपीय विमानन कंपनियों के साथ साथ दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे पश्चिमी एशिया के देशों की विमानन कंपनियों पर भी लागू होगा। यूरोप में कोरोनावायरस के चलते एक दिन में सबसे अधिक मौत होने के बाद सरकार ने हालिया निर्देश जारी किए हैं। अमेरिकी सरकार ने भी अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के देशों के बीच सभी यात्री उड़ानों को रद्द कर दिया है।

वर्तमान में एयर इंडिया एकमात्र भारतीय कंपनी है जो यूरोप के लिए हवाई यात्रा उपलब्ध कराती है। वहीं, इंडिगो तुर्की के लिए विमानन सेवा देती है।

अब भी 60 हजार लोग कर रहे तिरुमला के दर्शन

टी ई नरसिम्हन

देश भर में लोग कोरोनावायरस फैलने के डर से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जमा होने से भले ही कतरा रहे हों लेकिन आंध्र प्रदेश के तिरुमला स्थित बालाजी मंदिर का दृश्य बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। इस वायरस के फैलने के बाद से हर दिन यहां 60 हजार से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन 1 मार्च को मंदिर पहुंचने वाले 83,521 श्रद्धालुओं की तुलना में अब कुछ कमी आई है जिसकी एक प्रमुख वजह तमिलनाडु में बोर्ड की परीक्षाएं हैं।

तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के मुताबिक 14 मार्च को 78,872 श्रद्धालुओं ने करीब छह घंटे के इंतजार के बाद दर्शन किए जबकि 13 मार्च को छह घंटे के इंतजार के बाद 56,107 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। मंदिर का प्रबंध देखने वाला टीटीडी कोरोनावायरस को रोकने के उपाय कर रहा है। इसने विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से भारत आने के बाद 28 दिनों तक तिरुमला नहीं आने की अपील की है।

दुनिया भर में इस वायरस का प्रसार फरवरी में शुरू हुआ था और लोगों को सार्वजनिक जगहों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, कंपनियां कर्मचारियों को घर से ही काम करने के लिए कह रही हैं। फरवरी के आरंभ में मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 59,015 रही थी। दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को तीन घंटे से लेकर 10 घंटे तक का इंतजार करना होता है।

मंदिर के आसपास कई जगहों पर थर्मल स्कैनिंग की सुविधा दी जा रही है

टीटीडी के कार्यपालक अधिकारी अनिल कुमार सिंघल ने कहा कि संस्था ने कोरोनावायरस के प्रभाव को रोकन के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं।

कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने की राज्य और केंद्र सरकार की पहल के तौर पर अलीपीरी चेक प्वाइंट पर एक जागरूकता और सलाह केंद्र बनाया गया है। इसी तरह से अलीपीरी चेक प्वाइंट और दूसरी जगहों पर कोरोनावायरस रोकथाम कैंप बनाए गए हैं जिनमें थर्मल स्कैनिंग की सुविधा दी गई है।

उन्होंने कहा, 'यदि किसी श्रद्धालु में इसका लक्षण नजर आया तो उसे तिरुमला में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा और रुइया अस्पताल के अलगाव वार्ड (आइसोलेशन वार्ड) में भेजा जाएगा।'

अधिकारी ने कहा कि सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और तिरुमला में हर दो घंटे पर सफाई की जा रही है।

संकट में ग्राहकों को संदेश देते ब्रांड

कई ब्रांड परामर्श भरे गंभीर संदेश दे रहे हैं मगर कुछ हास्य का भी ले रहे हैं सहारा

सोहिनी दास

दुनिया भर में कोरोनावायरस (कोविड-19) का कहर बरपा हुआ है ऐसे में कई ब्रांडों ने लोगों को जागरुक करने की मुहिम छेड़ दी है। वैश्विक संकट के इस दौर में ब्रांड ग्राहकों का साथ खड़े नजर आ रहे हैं।

हाइजिन ब्रांडों ने तेजी दिखाते हुए कई चेतावनी और परामर्श दिया है। रेकिट बेंकाइजर ने अपने ब्रांड डिटॉल के लिए पैगाम-ए-सेहत नाम का विज्ञापन अभियान शुरू किया है। कंपनी का कहना है कि इसे उम्मीद है कि लक्षित ग्राहकों के बीच व्यवहार में बदलाव आएगा। फिलहाल कंपनी देश भर के 550,000 मदरसा स्कूलों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। आरबी हेल्थ इंडिया के बाहरी मामलों और साझेदारी निदेशक रवि भटनागर कहते हैं, 'इस साल हम सामूहिक समुदायिक कोशिशों केजरिये व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि इस कोशिश से जागरुकता लाने में तेजी आएगी और स्वच्छता तथा स्वास्थ्य से जुड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।' कई कंपनियों और ब्रांड विशेषज्ञों का कहना है कि सैनिटाइजर, कीटाणुनाशक, स्वास्थ्य सेवा और वेलनेस ब्रांडों की ऐसे वक्त में अहम भूमिका हो जाती है क्योंकि इनकी वजह से लोगों की घबराहट कम होती है और इस प्रक्रिया में कारोबारी फायदा भी हो जाता है। हालांकि जिन ब्रांडों का ताल्लुक हाइजीन से नहीं होता उनका जोर भी स्वच्छता पर होता है। मसलन अमूल, जोमैटो, जियो सिनेमा कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल स्वच्छता पर बात करने के लिए किया है। रेस्तरां और फूडटेक ब्रांड अपने ऑनलाइन चैनलों का इस्तेमाल उन सुरक्षा प्रोटोकॉल पर जोर देने के लिए कर कर रहे हैं जिनका वे अनुसरण करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि ग्राहक उनके पास आएंगे और उनका कारोबार चलता रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड (आईआईएचबी) चीफ मेंटर संदीप गोयल कहते हैं, 'सबसे अहम बात यह है कि इसमें कोई हास्य-व्यंग्य का मुद्दा नहीं है। पूरी सूचना और सामग्री सकारात्मक और आशावादी होना चाहिए।'

तकनीकी ब्रांड और सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों ने लोगों को भ्रामक सूचनाओं से बचने की सलाह दी है और कोरोनावायरस संकट से जूझ रहे देशों में संवाद बढ़ाने की कोशिश की है। ट्विटर की टाइमलाइन पर एक पोस्ट में लिखा है, 'हम आपको विश्वसनीय सूचनाएं, खासतौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी सूचनाएं देने में मदद करना चाहते हैं। हमने दुनिया के कुछ प्रमुख देशों में अपने सर्च में कुछ बदलाव किए हैं ताकि जब आप कोरोनावायरस सर्च करें तब स्वास्थ्य से जुड़े आधिकारिक स्रोतों का भी पता लग सके।'

गूगल के सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर यह संदेश दिया है कि उनकी कंपनी इस संकट से निपटने के लिए कैसी कोशिश कर रही है। उन्होंने लिखा, 'हम उन कारोबार और स्कूलों की मदद करना चाहते हैं जो कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं। इसकी शुरुआत हम इस हफ्ते ही करने जा रहे हैं। हम अपने एडवांस हैंगआउट्स मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल मुफ्त करने जैसी सेवाएं वैश्विक स्तर पर सभी जी स्वीट ग्राहकों को देंगे।'

अमूल ने वायरस पर विज्ञापन दिए। नेटफ्लिक्स, महाराष्ट्र सरकार ने हास्य संदेश दिया

ट्रैवल और पर्यटन उद्योग पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है लेकिन इस क्षेत्र की कंपनियों को यह सुनिश्चित करना है कि इस संकट से ग्राहकों के साथ उनके ताल्लुक पर असर नहीं पड़ना चाहिए। मेकमाईट्रिप के ग्रुप सीईओ राजेश मग्गो ने कहा, 'सरकार ने कुछ अपवादों को छोड़कर सभी वीजा को रद्द करने का फैसला किया है ऐसे में 110 प्रभावित देशों से आ रहे लोगों पर ध्यान देना जरूरी है।' इंडिगो और स्पाइसजेट ने कहा है कि वे यात्रा की तारीख में बदलाव के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे। कुछ ब्रांडों ने हल्के फुल्के अंदाज में संदेश देने की कोशिश की है। अमूल ने भी स्वच्छता का संदेश अपनी अनूठी शैली में दिया है। जिसमें कहा गया है, 'बेटर साफ (क्लीन) दैन सॉरी!' फिनटेक ब्रांड पेटीएम ने ऑनलाइन लेन-देन पर जोर देते हुए संदेश दिया है, 'स्टे सेफ पेटीएम करो' यानी सुरक्षित रहें और पेटीएम करें। फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने लोगों को खाना खाने से पहले हाथ धोने को कहा है। इसके ट्विटर संदेश को बेहद छोटे फॉन्ट में लिखा गया है ताकि किसी को जूम करके पढ़ना पड़े। इसके जरिये कंपनी यह संदेश दे रही है कि लोग एहतियात नहीं बरतने और साफ-सफाई पर ध्यान नहीं देने पर सूक्ष्म कीटाणुओं की जद में आ जाते हैं।

गोयल का कहना है कि ऐसे वक्त में उन सूचनाओं को देने से बचना चाहिए जिसके बारे में विस्तार से बात नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा, 'ब्रांड या तो संभावित समाधान का हिस्सा बनें या फिर चुप्पी साधे रहें।'